

देश दर्पण संवाद

— राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक — हम खबर नहीं, आईना दिखाते है



अपने लेख या सुझाव भेजने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें

इंदौर, मध्य प्रदेश सोमवार 28 सितंबर 2026, आश्विन कृष्ण पक्ष - 2, 2083, वर्ष - 1, अंक - 03, पृष्ठ - 8 , मूल्य - ₹ 2

खरारखरा

18 कैरेट : ₹1,14,660
22 कैरेट : ₹1,40,100
24 कैरेट : ₹1,52,830



इच्छाशक्ति:-
द्रढ़ इच्छाशक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों की दिशा में भी आगे बढ़ कर उन्हें पूर्ण कर सकता है। परमहंस योगानंद जी

सकारात्मक सोमवारसर:

प्रिय पाठकों,
सप्रेम नमस्कार! शुभसोमवार! आज 'देश दर्पण संवाद' के सफर का यह तीसरा सोमवार है, और हमें आपके हाथों में अपना यह तीसरा अंक सौंपते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। पिछले दो अंकों को आप सभी का जो अपार स्नेह, विश्वास और सकारात्मक मार्गदर्शन मिला है, उसने निष्पक्ष पत्रकारिता के प्रति हमारे संकल्प को और भी दृढ़ किया है। पहले और दूसरे अंक की सफलता आपके समर्थन के बिना संभव नहीं थी, और इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। एक नए सप्ताह की इस नई सुबह में, हम फिर से पूरे उत्साह के साथ आपके सामने ताजा, सटीक और बेबाक खबरें लेकर उपस्थित हैं। हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि हम आपके आस-पास की हर उस खबर और मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं, जिसका सीधा सरोकार आपसे और समाज से है। इस नए सप्ताह के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ। आशा है कि यह सप्ताह आपके जीवन में नई ऊर्जा, सफलता और सकारात्मकता लेकर आएगा। 'देश दर्पण संवाद' के साथ इसी तरह अपना जुड़ाव बनाए रखें। आपके बहुमूल्य सुझाव ही हमारी असली ताकत हैं। कृपया अपने विचार हम तक निरंतर पहुंचाते रहें, ताकि हम हर कदम पर और बेहतर बन सकें। आपका दिन और सप्ताह मंगलमय हो!

अनंत आनंद से रोशन हुआ इंदौर: 103 साल पुरानी परंपरा में उमड़ा लाखों का जनसैलाब

इंदौर में हुकुमचंद मिल से शुरू हुआ कारवां आज भी है शहर की धड़कन; 22 से अधिक भव्य झांकियों और अखाड़ों में महिलाओं के करतबों ने मोहा मन



इंदौर की 103 साल पुरानी ऐतिहासिक अनंत चतुर्दशी झांकी परंपरा ने एक बार फिर पूरे शहर को भक्ति, रोशनी और उत्साह के आनंद से सराबोर कर दिया। 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) की शाम से शुरू हुआ यह भव्य चल समारोह पूरी रात चलता रहा, जिसमें लाखों की संख्या में उमड़े जनसैलाब ने इस अनूठी और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का गवाह बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐतिहासिक शुरुआत और खजराना गणेश की अगुवाई इस गौरवशाली परंपरा की नींव आज से एक सदी पहले, वर्ष 1923 में सेठ हुकुमचंद की 'हुकुमचंद मिल' से रखी गई थी। कपड़ा मिलों के उस सुनहरे दौर से शुरू हुआ यह कारवां आज इंदौर की सबसे बड़ी और अटूट सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। शुक्रवार की शाम ठीक 6 बजे चिकमंगलूर चौराहे

से इस भव्य समारोह का आरंभ हुआ। परंपरा के अनुसार, सबसे पहली झांकी ऐतिहासिक खजराना गणेश मंदिर की रही। जैसे ही खजराना गणेश की झांकी आगे बढ़ी, ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा शहर ही आस्था के वशीभूत होकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ा हो। भव्य झांकियां और शहर के मार्गों पर स्वागत इस वर्ष के चल समारोह में 22 से अधिक भव्य झांकियां शामिल हुईं। रोशनी और उल्लास का यह कारवां डीआरपी लाइन और चिकमंगलूर चौराहे से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों—जेल रोड, एमजी रोड, कृष्णपुरा, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग और खजूरी बाजार होते हुए ऐतिहासिक राजवाड़ा पहुंचा। पूरे मार्ग में 100 से अधिक मंचों से इस भव्य चल समारोह का पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस उत्सव में हर वर्ग शामिल हुआ; जहां बच्चे

अपने परिजनों के कंधों पर बैठकर झांकियों को निहार रहे थे, वहीं युवा अपने मोबाइल कैमरों में इस अद्भुत खूबसूरती को कैद करते नजर आए। मुख्य आकर्षण: चांद पर गणपति और अखाड़ों का शौर्य झांकियों में आधुनिकता और पौराणिक कथाओं का बेजोड़ संगम देखने को मिला। इस बार 'चांद पर सवार गणपति' और 'बाबा महाकाल के दर्शन' जैसी जीवंत झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। धार्मिक प्रसंगों के अलावा इन झांकियों के माध्यम से समाज को महत्वपूर्ण संदेश भी दिए गए। जुलूस के साथ चल रहे पारंपरिक अखाड़ों ने समारोह की भव्यता में चार चांद लगा दिए। पहलवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र वहीं महिलाएं और बच्चियां, जिन्होंने शस्त्र संचालन के अद्भुत और हैरतअंगेज करतब दिखाकर नारी शक्ति

का शानदार उदाहरण पेश किया। चाक-चौबंद प्रशासनिक व्यवस्था इस ऐतिहासिक आयोजन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस द्वारा पूरे रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से पेनी नजर रखी गई। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से 'शक्ति दल' की तैनाती की गई थी। इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और आयोजन की पारंपरिक गरिमा को बनाए रखने के लिए डीजे (DJ) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहा। एक सदी से भी ज्यादा पुरानी इस परंपरा की रात में शहर सिर्फ मूक दर्शक नहीं रहा, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा और उल्लास के साथ इस महान उत्सव का हिस्सा बना।

गुलमर्ग परिसर में 'गुलमर्ग के राजा' का भव्य समापन, 21 पौधे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश



इंदौर के गुलमर्ग परिसर में बाल समिति द्वारा आयोजित 'गुलमर्ग के राजा' गणेश महोत्सव बेहद हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। उत्सव के दौरान पूरा परिसर सुंदरकांड, लाइव म्यूजिक, भजन संघा और महाआरती जैसे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुंजाता रहा। बच्चों की प्रतिभा निखारने के

लिए समिति ने चित्रकला, चेयर रेस और स्प्रून रेस जैसी कई मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित कीं, जिनमें सभी ने पूरे उत्साह से भाग लिया। इसके अलावा 'बप्पा 2026 मोमेंट' के तहत रहवासियों ने सोशल मीडिया पर भी अपने खूबसूरत पल साझा किए। इस बार उत्सव में भक्ति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का अनूठा

संगम भी देखने को मिला। गुलमर्ग परिसर युवा समिति ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए 24 सितंबर 2026 को 'हरियाली से ही खुशहाली' और 'पेड़ लगाएं, धरती बचाएं' का संदेश देते हुए 21 पौधे लगाने का जिम्मा उठाया। युवाओं की इस पहल को खूब सराहा गया। महोत्सव के अंतिम दिन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में विशाल भंडारे और महाप्रसादी के बाद सभी रहवासियों ने 'गणपति बप्पा मोरया, गुलमर्ग के राजा की जय' के जयघोष के साथ बप्पा को भावभीनी विदाई दी।

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण में सुधारवन्यजीव प्रेमियों के लिए सुखद खबर



विलुप्त होने की कगार से लौटा रेगिस्तानी हिरण 'अरेबियन ओरिक्स'रियाद;वैश्विक पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र से एक बेहद सुखद और सकारात्मक खबर सामने आई है। कभी जंगलों से पूरी तरह विलुप्त (Extinct in the Wild) मान लिए गए अत्यंत खूबसूरत और दुर्लभ रेगिस्तानी हिरण 'अरेबियन ओरिक्स' के कुनबे में शानदार सुधार दर्ज किया गया है। सऊदी अरब और खाड़ी देशों द्वारा पिछले कुछ दशकों से चलाए जा रहे सघन कृत्रिम प्रजनन (Captive Breeding) और पुनर्वास कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की हालिया

समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अरेबियन ओरिक्स की आबादी में हुई इस सतत वृद्धि को देखते हुए इसे अब अति-संकेतग्रस्त की सूची से बाहर कर दिया गया है। वन्यजीव वैज्ञानिकों ने इसे सदी के सबसे सफल संरक्षण अभियानों में से एक बताया है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों से भी पर्यावरणविदों के लिए एक अच्छी खबर आई है, जहां पिछले 50 वर्षों से गायब मानी जा रही देश की दूसरी सबसे छोटी कंगारु प्रजाति 'नाबारलेक' (Nabarlek) को वाइल्डलाइफ कैमरों में दोबारा जीवित और सक्रिय पाया गया है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में इन दोनों ही खबरों ने वैश्विक स्तर पर नया उत्साह जगाया है।

भारतीय रेलवे का 'ग्रीन गियर': एक बार टैंक फुल, 2200 किमी दौड़ेगी देश की पहली LNG ट्रेन; अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी

भारतीय रेलवे की पटरियों पर अब सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि बदलाव की बयार भी दौड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह महज एक इंजन की शुरुआत नहीं है, बल्कि प्रदूषण से आजादी और ईंधन की बचत की दिशा में भारत की एक बड़ी छलांग है। इस नई ट्रेन की तकनीक और ताकत दोनों ही हैरान करने वाली हैं। जरा सोचिए, एक बार इसका एलएनजी टैंक फुल हो जाए, तो यह बिना रुके 2200 किलोमीटर तक का लंबा

सफर तय कर सकती है। यानी बीच रास्ते में बार-बार ईंधन भरने का झंझट पूरी तरह खत्म और माल ढुलाई या सफर की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। सबसे दिलचस्प बात इस ट्रेन के स्मार्ट इंजन की है। इसे पूरी तरह से 'डुअल-फ्यूल तकनीक' पर तैयार किया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह इंजन परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। अगर लंबे सफर के दौरान गैस कम पड़ने लगे, तो ट्रेन को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आधुनिक सिस्टम बिना किसी झटके के चलते सफर में ही खुद को एलएनजी से डीजल मोड पर शिफ्ट कर लेगा। यह खूबी इसे भारतीय

रेलवे के सबसे भरोसेमंद और एडवांस इंजनों की कतार में खड़ा करती है। यह खबर सिर्फ रेलवे के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर देश की हवा और खजाने दोनों पर पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि एलएनजी, पारंपरिक डीजल की तुलना में काफी सस्ती पड़ती है और इससे धुआं या कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर होता है। डीजल के बजाय गैस से ट्रेन दौड़ाने पर जहां एक तरफ रेलवे के ईंधन बिल में करोड़ों रुपये की भारी बचत होगी, वहीं विदेशी कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता भी घटेगी। साफ शब्दों में कहें तो यह नई एलएनजी ट्रेन पर्यावरण के लिए



डिजिटल पेमेंट पर ब्रेक: इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में दिखा सबसे ज्यादा विरोध, कैश की तरफ लौटे लोग



भोपाल। मध्य प्रदेश में डिजिटल भुगतान प्रणाली के खिलाफ मनाए गए 'नो यूपीआई डे' (No UPI Day) का पूरे प्रदेश में जबरदस्त असर देखने को मिला है। कैशलेस इकॉनमी के इस दौर में जब लोग अपनी जेब में नकदी रखना लगभग भूल चुके हैं, इस विरोध ने बाजारों की तस्वीर बदलकर रख दी। प्रदेश भर में यूपीआई (UPI) के जरिए होने वाले रोजमर्रा के लेनदेन में अचानक 25 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस मुहिम ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यापारी वर्ग और आम लोगों में भुगतान प्रणाली की कुछ नीतियों को लेकर गहरा रोष है। प्राप् जानकारी के अनुसार, इस सांकेतिक विरोध का सबसे ज्यादा प्रभाव प्रदेश के बड़े व्यापारिक केंद्रों— इंदौर, राजधानी भोपाल और ग्वालियर में देखने को मिला। इन तीनों महानगरों में विरोध

की तीव्रता अन्य शहरों और कस्बों की तुलना में कहीं अधिक रही। सुबह से ही बाजारों में अधिकांश दुकानदारों ने अपने काउंटरों से क्यूआर कोड (QR Code) स्कैनर हटा दिए थे या उन्हें पलट कर रख दिया था। ग्राहकों से स्पष्ट तौर पर केवल नकद भुगतान (कैश पेमेंट) का ही आग्रह किया जा रहा था। चाय-पान की गुमटियों, स जी मंडियों से लेकर बड़े-बड़े शोरूम तक में 'आज यूपीआई बंद है' जैसी सूचनाएं देखने को मिलीं। इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ा जो बिना नकदी लिए सिर्फ स्मार्टफोन के भरोसे खरीदारी करने निकले थे। कई जगहों पर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच हल्की बहस भी देखने को मिली, लेकिन अंततः लोगों को एटीएम (ATM) की तरफ दौड़ लगानी पड़ी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस विरोध

ने एक बड़े वित्तीय आंकड़े को प्रभावित किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में हर महीने यूपीआई के माध्यम से लगभग 63 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम कारोबार होता है। ऐसे में एक दिन के भीतर लेनदेन में 25 फीसदी की कमी आना अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर के लिए खतरे की घंटी है। बाजार के जानकारों का मानना है कि यदि यह विरोध आगे भी जारी रहा या इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, तो राज्य के व्यापारिक चक्र पर इसका बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। व्यापारिक संगठनों के सूत्रों की मानें तो यह विरोध मुख्य रूप से सर्वर की लगातार रहने वाली समस्याओं, लेनदेन के बाद खातों में पैसा देर से पहुंचने (सेटलमेंट में देरी) और भविष्य में यूपीआई पर लगने वाले संभावित शुल्कों (एमडीआर चार्जस) की आशंका के चलते पनपा है। 'नो यूपीआई डे' के जरिए व्यापारियों ने सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और पेमेंट कंपनियों को एक कड़ा संदेश दिया है। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के बाजारों से उठी इस आवाज ने साबित कर दिया है कि 63 हजार करोड़ के मासिक कारोबार वाले इस राज्य में बिना व्यापारियों के भरोसे के शत-प्रतिशत डिजिटल अर्थव्यवस्था का सपना साकार नहीं हो सकता। समय रहते इस सिस्टम की तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है।

श्रीअन्न उत्पादन में अग्रणी बना सीधी जिला,

कोदो-कुटकी जैसी मिलेट फसलें हैं संस्कृति की पहचान: डॉ. मोहन यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश का सीधी जिला 'श्रीअन्न' (मोटें अनाज) के उत्पादन में प्रदेश का सिरमौर बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले की इस कृषि उपलब्धि की सराहना करते हुए इन फसलों को स्थानीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया है। 'कृषक कल्याण वर्ष 2026' और 'बलराम कृषि महोत्सव' के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीधी जिले में पीढ़ियों से मिलेट फसलों की खेती होती आ रही है।

जिले में पारंपरिक रूप से कोदो, कुटकी, सांवा, मिजरी और काकुन जैसी कई पौष्टिक फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि श्रीअन्न की यह खेती केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिले की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। इन फसलों को बढ़ावा देने से न केवल किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि विविधता को भी एक नई पहचान मिल रही है।



विकास की दोहरी उड़ान: ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम हब,

गडकरी करेंगे 'सुगम परिवहन सेवा' का शुभारंभ

भोपाल। मध्य प्रदेश अब औद्योगिक विकास और उन्नत परिवहन के मोर्चे पर लंबी छलांग लगाने जा रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योग जगत का भरोसा मजबूत हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को जल्द ही बेहतर यातायात की बड़ी सौगात मिलने वाली है। ग्वालियर बनेगा नया इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में निवेश का माहौल लगातार बेहतर हो रहा है। हाल ही में बैंगलुरु में देश के दिग्गज उद्योगपतियों के साथ हुई मुख्यमंत्री की सार्थक चर्चा ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। इस इन्वेस्टर मीट में ग्वालियर में प्रस्तावित 'टेलीकॉम मैनुफैक्चरिंग

जोन' को लेकर गहरा मंथन हुआ। उद्योग जगत ने इस प्रोजेक्ट में भारी उत्साह दिखाया है। यह जोन धरातल पर उतरते ही ग्वालियर को देश के प्रमुख टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में स्थापित कर देगा, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। **परिवहन में नए अध्याय की शुरुआत** औद्योगिक रफ्तार के साथ-साथ राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के दैनिक सफर को आसान बनाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे यहां राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'मुख्यमंत्री

सुगम परिवहन सेवा' का विधिवत शुभारंभ करेंगे। यह नई परिवहन सेवा प्रदेश के दूरदराज के इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ने और यात्रियों को एक सुरक्षित, सस्ती व सुलभ यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। **निष्कर्ष:** ग्वालियर में टेलीकॉम जोन के जरिए औद्योगिक निवेश और 'सुगम परिवहन सेवा' के जरिए शानदार कनेक्टिविटी; सरकार के ये दोनों कदम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जीवनशैली में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने वाले साबित होंगे।

शिक्षा विभाग की बड़ी पहल: मध्य प्रदेश में दो दिन के भीतर जारी हुए 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबित मामलों का त्वरित निराकरण करते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने पिछले दो दिनों के भीतर 600 अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। यह कदम दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को समय पर आर्थिक संबल और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के

करीब 859 प्रकरण लंबे समय से लंबित थे। मुख्यमंत्री की जन-कल्याणकारी सोच और अपेक्षा के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए, इनमें से 600 मामलों में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने इस निर्णय को 'संवेदनशीलता से समाधान' बताते हुए कहा कि इससे पीड़ित परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। आगामी दो दिनों में 30 और आदेश होंगे जारी शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है और आगामी दो दिनों में लगभग 30 और

अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। शेष बचे प्रकरणों के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार उन पर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ आवश्यक विकल्पों पर विचार कर रही है। राज्य सरकार का मुख्य प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी दिवंगत कर्मचारी के परिवार को अनावश्यक भत्ताकाव का सामना न करना पड़े और उन्हें जल्द से जल्द उनका अधिकार मिल सके।

दतिया का सियासी तिलिस्म : राजेंद्र भारती के बाद अब घनश्याम सिंह की विधायकी पर तलवार, क्या दतिया में फिर होगा उपचुनाव?



देश दर्पण संवाद / प्रकाश त्रिपाठी
दतिया / भोपाल

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट का राजनीतिक घटनाक्रम किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। 2023 के मुख्य विधानसभा चुनाव से

लेकर हालिया उपचुनाव तक, इस सीट पर लगातार अप्रत्याशित मोड़ आ रहे हैं। पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र भारती को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी और अब उपचुनाव जीतकर आए मौजूदा कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह की कुर्सी पर भी हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। दतिया के सियासी गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है— क्या इस सीट की जनता को एक ही कार्यकाल में तीसरी बार मतदान करना पड़ेगा? आखिरकार दतिया में चल क्या रहा है,

इसे सिलसिलेवार ढंग से समझना जरूरी है: राजेंद्र भारती के साथ क्या हुआ था?

साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने राज्य के तत्कालीन कद्दावर गृह मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा को 7,700 से अधिक मतों से करारी शिकस्त दी थी। लेकिन भारती का यह कार्यकाल लंबा नहीं चल सका। इसी साल अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत ने घोषाघड़ी के एक मामले में उन्हें तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत सजा का ऐलान होते ही भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई, जिसके चलते दतिया में उपचुनाव कराना पड़ा।

घनश्याम सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती

उपचुनाव में कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा, जिन्होंने 30 जुलाई 2026 को हुए मतदान के बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हरा दिया। लेकिन जीत का जश्न अभी ठीक से थमा भी नहीं था कि भाजपा नेता और अधिवक्ता दीपक बेलपत्री ने जबलपुर हाईकोर्ट में उनकी विधायकी को चुनौती दे दी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि घनश्याम सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में 1991 के एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई है। यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन और चक्काजाम से जुड़ा है, जिसमें 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें घनश्याम सिंह का नाम भी शामिल था। याचिकाकर्ता की मांग है कि आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के कारण उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए।

अपनों से घिरे घनश्याम, राजेंद्र भारती पर लगाए गंभीर आरोप

इस पूरे विवाद ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को भी सड़क पर ला दिया है। घनश्याम सिंह ने इस याचिका को विरोधियों की साजिश करार देते हुए इसके पीछे सोधे तौर पर पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती और

भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी का हाथ बताया है। घनश्याम सिंह का कहना है कि भारती ने उपचुनाव में भी उनके खिलाफ भीतरघात किया था। वहीं, राजेंद्र भारती ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए घनश्याम सिंह पर नरोत्तम मिश्रा से सांठगांठ का पुराना आरोप मह दिया है।

भाजपा में भी अंतर्कलह: नरोत्तम का दबदबा और आशुतोष खेने में बेंचैनी

दतिया की राजनीति केवल कांग्रेस के भीतर नहीं, बल्कि भाजपा के खेने में भी उलझी हुई है। नरोत्तम मिश्रा काटिकट करने के बाद भाजपा ने आशुतोष तिवारी पर दांव खेला था, लेकिन वे सीट नहीं निकाल पाए। उपचुनाव हारने के बाद पार्टी संगठन में एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा के कद को तरजीह दी जा रही है। ऐसे में हार के बावजूद आशुतोष समर्थकों को संगठन में महत्वपूर्ण पदों (जैसे अध्यक्ष पद) पर बनाए रखने या तबज्जो देने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का एक घड़ा लगातार सवाल खड़े कर रहा है। दतिया का वर्तमान परिदृश्य पूरी तरह से कानूनी दांव-पेंच और राजनीतिक प्रतिशोध में उलझ गया है। यदि जबलपुर हाईकोर्ट 35 साल पुराने मामले में तथ्य छिपाने के आरोप को गंभीर मानकर घनश्याम सिंह का निर्वाचन रद्द करता है, तो दतिया की जनता को एक बार फिर मतदान केंद्रों की कतार में लगना पड़ सकता है।

चुनाव आयोग में भारी घमासान

मुख्य आयुक्त के फैसलों पर उठे सवाल, वोटर लिस्ट को लेकर सरकार तक पहुंची शिकायत

नई दिल्ली।

हमेशा शांति से देश भर में चुनाव कराने वाला चुनाव आयोग आज खुद एक बड़े विवाद में घिर गया है। अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि चुनाव आयोग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आयोग के तीन सबसे बड़े अधिकारियों के बीच भारी अनबन है और यह मामला अब सरकार के सबसे बड़े अधिकारी (कैबिनेट सचिव) तक पहुंच गया है।

क्या है पूरा विवाद?

आसान भाषा में समझें तो चुनाव आयोग में तीन मुख्य अधिकारी होते हैं— एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्त। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त जगनेश कुमार के फैसलों पर 14 बार लिखित में अपना विरोध जताया है। इन दोनों का सीधा आरोप है कि मुख्य आयुक्त उन्हें बिना बताए, अकेले ही कई अहम फैसले ले रहे हैं।

वोटर लिस्ट को लेकर है सबसे बड़ी लड़ाई

इस पूरी कलह की सबसे बड़ी वजह हमारी और आपकी 'वोटर लिस्ट' है। रिपोर्ट के मुताबिक, दो आयुक्तों का कहना है कि वोटर लिस्ट बनाने के तरीके में गुपचुप तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों से पावर छीनकर सारा कंट्रोल दिल्ली (केंद्र) से करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा, नए वोटर कार्ड बनवाने वाले 'फॉर्म-6' में बिना कोई कानून बदले अपनी मर्जी से एक नया सवाल जोड़ दिया गया है, जिसे दोनों आयुक्तों ने नियमों के खिलाफ बताया है।

मामला पहुंचा कैबिनेट सचिव के पास

चुनाव आयोग के इतिहास में शायद यह पहली बार है जब विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों नाराज चुनाव आयुक्तों ने देश के सबसे बड़े नौकरशाह यानी 'कैबिनेट सचिव' को अलग-अलग चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि आयोग के आईटी सिस्टम (सॉफ्टवेयर) पर मनमाने तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है।

सियासत में आया उबाल

इस खबर के छपते ही देश की राजनीति गरमा गई है।



विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह सीधे-सीधे 'वोट चुराने' की तैयारी है। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसका बचाव किया है। बीजेपी का कहना है कि अगर अधिकारियों के बीच किसी बात पर असहमति है, तो

यह अच्छी बात है, यह साबित करता है कि वहां कोई तानाशाही नहीं चल रही है और हमारा लोकतंत्र जिंदा है। कुलमिलाकर, चुनाव आयोग जैसी पारदर्शी संस्था के अंदर से आई इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है और अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आगे क्या होता है।

मिशन-2027 के लिए भाजपा की नई ब्रिगेड तैयार

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने घोषित किए राज्यों के प्रभारी, दिग्गजों को अहम मोर्चों की कमान



नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। मिशन-2027 और उसके बाद की रणनीतियों को धार देने के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

इस नई टीम में अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और आक्रामकता का स्पष्ट समावेश देखने को मिल रहा है। नवीन के नेतृत्व में तैयार यह ब्रिगेड पूरी तरह से इलेक्शन मोड में नजर आ रही है।

इस बड़े संगठनात्मक बदलाव में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मध्य प्रदेश में संगठन की कमान त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बिप्लव कुमार देब को सौंपी गई है। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।

वामपंथी किला ढहाने वाले रणनीतिकार बिप्लव देब से पार्टी को उम्मीद है कि वे मध्य प्रदेश में भाजपा के आधार को और मजबूत करेंगे। वहीं, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभार पार्टी के दिग्गज रणनीतिकार विनोद तावड़े को सौंपा गया है।

पार्टी ने पूर्वकेंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे दो अहम राज्यों का प्रभारी बनाया है। चुनावी दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और अहम माने जाने वाले महाराष्ट्र का प्रभार बैजयंत जय पांडा को सौंपा गया है।

इसी तरह बिहार एवं कर्नाटक की जिम्मेदारी हरिथ द्विवेदी को और गुजरात की कमान तरुण चुध को दी गई है। पश्चिम बंगाल एवं तेलंगाना जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों का प्रभार सुनील बंसल को सौंपा गया है, जबकि राम माधव को तमिलनाडु एवं उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है।

राजधानी दिल्ली के लिए डॉ. विनय सहस्रबुद्धे को प्रभारी नियुक्त किया गया है। जम्मू-कश्मीर एवं पंजाब का

प्रभार डॉ. सतीश पूनिया, राजस्थान का संजय भाटिया और ओडिशा का प्रभार डी. पुरदेश्वरी को सौंपा गया है। इस फेरबदल में मध्य प्रदेश के नेताओं का भी राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ाया गया है। पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को आंध्र प्रदेश का और सांसद गजेन्द्र पटेल को झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राजस्थान की सह-प्रभारी और पूर्व मंत्री लाल सिंह

आर्य को पश्चिम बंगाल का सह-प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा मप्र के आशीष अग्रवाल को पार्टी का राष्ट्रीय मीडिया संयोजक नियुक्त किया गया है। इन नई नियुक्तियों के साथ ही भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब नए प्रभारियों के सामने राज्य इकाइयों को एकजुट कर

2027 के महासमर के लिए गोस जमीन तैयार करने की अहम चुनौती होगी।



भोपाल मास्टर प्लान

भोपाल मास्टर प्लान: ड्राफ्ट प्रकाशन को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, व्यावसायिक गतिविधियों पर सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी संपत्ति या निर्माण कार्य की वैधता मौजूदा मास्टर प्लान (2005) और वर्तमान में लागू भवन निर्माण नियमों के आधार पर ही तय की जाएगी।

राजधानी भोपाल के लिए पिछले 21 सालों से बहुप्रतीक्षित नए मास्टर प्लान का रास्ता आखिरकार साफ होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि, रियायती इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले कारोबारियों को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि नए ड्राफ्ट में 'लैंडयूज' (भू-उपयोग) में बदलाव का कोई प्रस्ताव आता भी है, तो भी सीलिंग की कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी और यह बदस्तूर जारी रहेगी। मामले की आगामी सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।

वर्तमान नियमों के आधार पर तय होगी वैधता

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी संपत्ति या निर्माण कार्य की वैधता मौजूदा मास्टर प्लान (2005) और वर्तमान में लागू भवन निर्माण नियमों के आधार पर ही तय की जाएगी। जब तक नया मास्टर प्लान अंतिम रूप से लागू नहीं हो जाता, तब तक सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। न्यायालय के आदेशानुसार, जिन इलाकों का लैंडयूज स्पष्ट रूप से 'रियायती' है, वहां किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां स्वीकार्य नहीं होंगी। ऐसे स्थानों पर डिमोलिशन या सीलिंग की कार्रवाई बिना किसी बाधा के संचालित की जाएगी। सीलिंग में लापरवाही पर न्यायालय सख्त, सरकार ने वापस लिया **समिति का फैसला** सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि नगर निगम द्वारा सील की गई दुकानें सुबह बंद रहती हैं, लेकिन शाम होते ही पुनः खुल जाती हैं। न्यायालय ने इस 'पिक एंड चूज़' की नीति और लापरवाही पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय के सख्त

रुख को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सीलिंग मामले की जांच हेतु गठित की गई अपनी नई समिति का फैसला वापस ले लिया है। सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि सीलिंग की कार्रवाई में यह समिति किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगी।

विवाद का पृष्ठभूमि

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भोपाल नगर निगम ने अगस्त माह में रियायती इलाकों में संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई प्रारंभ की थी। इस अभियान के तहत शहर में लगभग 8,084 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए थे और करीब 190 दुकानों को सील किया गया था। व्यापारियों के कड़े विरोध के बाद सरकार ने एक जांच समिति गठित कर दी थी, जिसके कारण पिछले 22 दिनों से सीलिंग की कार्रवाई रुकी हुई थी। अब न्यायालय के नवीनतम आदेश के बाद नगर निगम द्वारा सीलिंग की कार्रवाई पुनः शुरू की जाने की संभावना है।

आगामी कदम

ड्राफ्ट का प्रकाशन: राज्य सरकार अब मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रकाशित कर सकेगी, लेकिन इसके अंतिम प्रकाशन (मंजूरी) से पूर्व सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना अनिवार्य होगा।

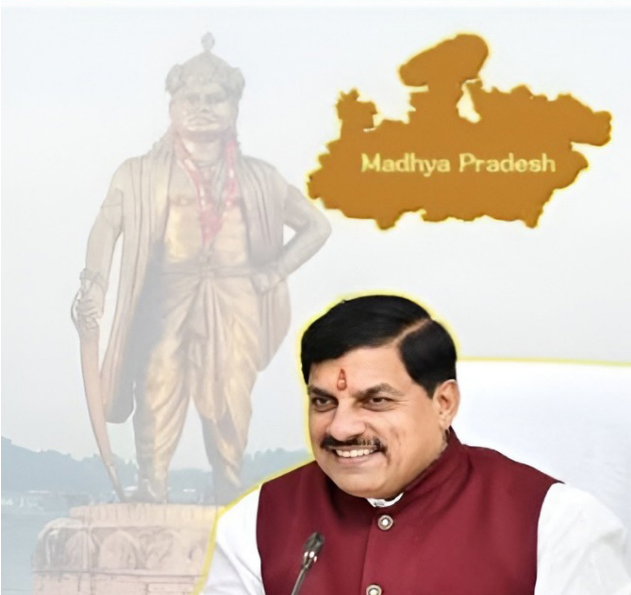
मिश्रित भू-उपयोग पर स्थिति: न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जिन इलाकों का लैंडयूज स्पष्ट नहीं है या जहां 'मिश्रित भू-उपयोग' (मिक्स्ड लैंडयूज) है, वहां फिलहाल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आगामी सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है।

इस सुनवाई से एक सप्ताह पूर्व सरकार और नगर निगम को अपनी अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी।

भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी

रहवासी इलाके में कारोबार नहीं



भारत का बढ़ता रक्षा निर्यात:

स्वदेशी हथियारों का बजा डंका



'भारत बना दुनिया का बड़ा

हथियार सप्लायर, 80 से ज्यादा

देशों को भेज रहा हथियार'

● मयंक आनंद

हाल के वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात (Defence Exports) में तेज बहोतरी देखी गई है। देश में बने स्वदेशी हथियार अब भारत की वैश्विक रक्षा बिक्री का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ब्रह्मोस, आकाश से लेकर पिनाका तक, ये सभी प्लेटफॉर्म भारत के रक्षा निर्माण और निर्यात के दायरे को तेजी से बढ़ा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ के रक्षा निर्यात के बाद, भारत ने 2026-27 में भी अपने इस इकोसिस्टम को मजबूत करना जारी रखा है।

अगस्त 2026 में रक्षा मंत्रालय ने प्रक्रियाओं को आसान बनाने और भारतीय कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच तेज करने के लिए 'डिफेंस एक्सपोर्ट एसओपी' और 'ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस' (OGEL) फ्रेमवर्क में ढील दी। नए नियमों के तहत OGEL की वैधता दो से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई और इसका दायरा भी बढ़ाया गया, हालांकि संवेदनशील देशों और उपकरणों के लिए सुरक्षा मानकों को बरकरार रखा गया है।

सरकार ने 2029 तक **₹50,000 करोड़** के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त में बताया कि भारत में अब 145 रक्षा निर्यातक हैं जो 80 से अधिक देशों को अपने उत्पाद बेच रहे हैं। सरकार का बड़ा लक्ष्य समय से पहले ही घरेलू रक्षा उत्पादन को ₹3 लाख करोड़ और निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुंचाना है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए ₹7.85 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसमें से ₹2.19 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च (कैपिटल हेड) के लिए है।

पूंजीगत खरीद के इस बजट में से ₹1.39 लाख करोड़ केवल घरेलू उद्योगों से खरीदारी के लिए तय किए गए हैं, ताकि घरेलू जरूरतों के साथ-साथ निर्यात के लिए भी एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार किया जा सके।

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा रक्षा निर्यात

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹23,622 करोड़ की तुलना में 62.66% अधिक है।

सरकार ने बताया कि भारतीय रक्षा उपकरण अब 80 से अधिक देशों में जा रहे हैं और निर्यातकों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। इसके साथ ही, FY2025-26 में घरेलू रक्षा उत्पादन भी ₹1.78 लाख करोड़ के ऑल-टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों और विदेशी ग्राहकों दोनों के लिए एक बड़ा आधार तैयार हुआ है।

मिसाइल निर्यात में ब्रह्मोस सबसे आगे

ब्रह्मोस भारत के सबसे प्रमुख रक्षा निर्यात उत्पादों में से एक है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के डीआरडीओ (DRDO) और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है।

फिलिपिंस और वियतनाम इसके प्रमुख खरीदार बनकर उभरे हैं, जबकि इंडोनेशिया ने भी इस मिसाइल प्रणाली को खरीदने में रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस की बढ़ती मांग इस बात का सबूत है कि भारत अब बड़े हथियार आयात करने वाले देश से निकलकर जटिल रक्षा तकनीक निर्यात करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।

आकाश ने खोला एयर डिफेंस मार्केट

भारत का निर्यात पोर्टफोलियो केवल आक्रामक मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। 'आकाश' वेपन सिस्टम ने भारतीय रक्षा उपकरणों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार का एक नया रास्ता खोला है।

डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश एक 'सरफेस-टू-एयर' (सतह से हवा में मार करने वाली) मिसाइल प्रणाली है, जो विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों को नाकाब करने के लिए बनाई गई है। साल 2022 में समझौता करने के बाद आर्मेनिया इसका पहला विदेशी ग्राहक बना, जिसे 2024 से डिलीवरी शुरू कर दी गई थी।

पिनाका भी बढ़ा रहा दायरा

पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्जर भी भारत के बढ़ते निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आर्मेनिया ने 2022 में पिनाका सिस्टम के लिए सौदा किया था और जनवरी 2026 में गाइडेड संस्करण की पहली खेप उसे भेज दी गई।

भारत में निर्मित यह सिस्टम गाइडेड और एक्सटेंडेड-रेंज रॉकेट सहित कई अलग-अलग वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका निर्यात दिखाता है कि स्वदेशी प्रणालियों की मांग अब दुनिया भर में बढ़ रही है।

दक्षिण-पूर्व एशिया की बढ़ती अहमियत

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र भारतीय रक्षा निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। रिपोर्टों के अनुसार, 2020 से 2025 के दौरान भारत के कुल रक्षा निर्यात में म्यांमार, फिलीपींस और वियतनाम की हिस्सेदारी 70.1% रही।

यह बढ़ती दर्याती है कि विदेशी देश अपने रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में विविधता ला रहे हैं और भारतीय प्रणालियों पर भरोसा जता रहे हैं।

भारत के लिए इस निर्यात प्रोत्साहन का सीधा संबंध घरेलू रक्षा उत्पादन को मजबूत करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और आयातित सैन्य उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करने से है।



प्रधान संपादक असित पाठक की कलम से...

भारत का युवा और कार्यशील वर्ग — देश के भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति

प्रथम दो अंकों में मैंने एक नए समाचार पत्र की आवश्यकता तथा हमारे संकल्पों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हमने यह बताने का भी प्रयास किया कि उन आवश्यकताओं और संकल्पों की पूर्ति के लिए 'देश दर्पण संवाद' क्या कर रहा है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अब मैं अपने पसंदीदा विषय—भारत का युवा और भारत का कार्यशील वर्ग—पर अगले दो अंकों में विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ।

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े जनसमूह वाला देशों में है। हमारी 140 से अधिक विशाल जनसंख्या में लगभग 10 करोड़ लोग 64 वर्ष की अधिक आयु के तथा नवजात शिशु से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे लगभग 30 करोड़ हैं।

मध्य में एक विशाल जन समूह जो 100 करोड़ से ज्यादा है और जिसे यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के अनुसार कार्यशील वर्ग कहा गया है तथा इसमें से भी 15 से 24 वर्ष की आयु के समूह के युवा लोग 25 करोड़ से ज्यादा हैं।

यही 100 करोड़ से अधिक लोगों का वह वर्ग है जो आज भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन और सामाजिक जीवन को आगे बढ़ा रही है और आने वाले दशकों में देश की दिशा को प्रभावित करेगी।

लेकिन यही शक्ति हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है और सबसे बड़ा अवसर भी।

यदि इस वर्ग को सही शिक्षा, कौशल, रोजगार, अवसर, मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण मिले, तो यही युवा भारत की विकास यात्रा को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसके विपरीत, यदि उनकी ऊर्जा और आकांक्षाओं को सही दिशा न मिले, तो निराशा, भ्रम और अवसरों की कमी गंभीर सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकती है।

इसलिए आज सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि भारत के पास कितने युवा हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि—

हम भारत के युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं?

सबसे पहले भारत के युवाओं को एक बात समझनी होगी

भारत केवल 140 करोड़ लोगों का समूह नहीं है। यह एक अत्यंत विशाल और जटिल व्यवस्था है। इस व्यवस्था में करोड़ों लोगों के लिए प्रतिदिन शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, आवास, बिजली, पानी, परिवहन, संचार, रोजगार और सुरक्षा जैसी अनगिनत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है।

और यह सब किसी एक संस्था या किसी एक सरकार के भरोसे नहीं चलता।

इसके पीछे केंद्र और राज्य सरकारों की व्यवस्थाएँ, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, किसान, श्रमिक, उद्यमी, पेशेवर, शिक्षक, चिकित्सक और करोड़ों सामान्य नागरिकों का योगदान होता है।

युवाओं को यह भी समझना होगा कि सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती।

सरकारी नौकरियों की अपनी एक सीमा है।

लेकिन सरकार विकास के माध्यम से रोजगार और आजीविका के अवसरों का एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर सकती है—सड़कें, रेलवे, उद्योग, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, निर्माण, ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, स्टार्टअप, MSME और अन्य क्षेत्रों में।

यही वह अंतर है जिसे हमारे युवाओं को समझना होगा—सरकार का काम केवल नौकरी देना नहीं है; सरकार का एक बड़ा दायित्व ऐसा वातावरण और ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना भी है, जिसमें करोड़ों रोजगार और उद्यम के अवसर पैदा हो सकें।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न

हम भारत में गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों के नाम जानते हैं।

लेकिन क्या हम उस मंत्रालय और उस व्यवस्था के मंत्रियों के बारे में उतनी ही गंभीरता से चर्चा करते हैं, जो देश के करोड़ों युवाओं और कार्यशील आबादी के कौशल, रोजगार और आजीविका से जुड़ी है?

आइए, अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि इस युवा और कार्यशील वर्ग के लिए हम क्या कर सकते हैं।

■ रोजगार के अवसर — सबसे बड़ी चुनौती : किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी युवा और कार्यशील आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। जैसा उपर जिक्र किया है सरकार की जिम्मेदारी है एक ऐसा तंत्र विकसित करने की जो रोजगार व्यवसाय के भरपूर अवसरों का सृजन कर सके।

■ शिक्षा के अवसर:- शिक्षा के क्षेत्र में बड़े शहरों और महानगरों में अनेक अच्छे संस्थान उपलब्ध हैं। लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

■ व्यावसायिक शिक्षा और स्वरोजगार : हर युवा को केवल सरकारी या निजी नौकरी तलाशने के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए कि

हमें ऐसी व्यावसायिक और उद्यमिता-आधारित शिक्षा की आवश्यकता है,

जिससे एक युवा स्वयं अपना छोटा व्यवसाय या रोजगार शुरू कर सके और आगे चलकर अपने साथ चार-पाँच या उससे अधिक लोगों को भी रोजगार दे सके।

एक नौकरी खोजने वाले युवा से कहीं अधिक शक्तिशाली है :- एक ऐसा युवा जो स्वयं रोजगार पैदा कर सके।

■ देशभर में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र : देश के प्रत्येक हिस्से में ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता है जहाँ शिक्षित युवाओं को उनकी रुचि और स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सके।

इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मशीन ऑपरेटर, वेल्डर, CNC ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर, पर्यटन और अनेक अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को देश और विदेश के रोजगार बाजार के लिए तैयार किया जा सकता है।

डिग्री के साथ कौशल—यही भविष्य की वास्तविक आवश्यकता है।

■ करियर काउंसलिंग को मजबूत करना : आज बहुत से युवा यह नहीं जानते कि उनकी योग्यता और रुचि के अनुरूप कौन-सा करियर उनके लिए उपयुक्त हो सकता है।

इसलिए बड़े स्तर पर करियर काउंसलिंग नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है।

विशेषज्ञ करियर काउंसलरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो युवाओं को केवल यह न बताएँ कि कौन-सी नौकरी उपलब्ध है, बल्कि यह भी समझाएँ कि—

- किस क्षेत्र में भविष्य के अवसर हैं,
- कौन-सा कौशल सीखना चाहिए,
- किस प्रकार का प्रशिक्षण आवश्यक है
- स्वरोजगार की क्या संभावनाएँ हैं,
- विदेशों में किन कौशलों की मांग है,
- और अपनी क्षमता के अनुसार करियर का रास्ता कैसे चुना जाए।

■ उद्योग और रोजगार सृजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना : यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में उद्योग, व्यापार, MSME, निवेश और रोजगार सृजन से संबंधित नीतियों और मंत्रालयों को सार्वजनिक विमर्श में अधिक महत्व मिलना चाहिए।

हमारे युवाओं और कार्यशील वर्ग को यह विश्वास महसूस होना चाहिए कि सरकार उनकी समस्याओं, उनकी आकांक्षाओं और उनके भविष्य को गंभीरता से देख रही है।

उन्हें यह भी दिखाई देना चाहिए कि देश में उद्योग लगाने, व्यवसाय शुरू करने, कौशल विकसित करने और रोजगार पैदा करने वालों के लिए

अवसरों का विस्तार हो रहा है।

जब युवा को अवसर दिखाई देता है, तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है।

और जब करोड़ों युवाओं में आत्मविश्वास पैदा होता है, तो वही आत्मविश्वास व उत्साह राष्ट्र की आर्थिक शक्ति बन जाता है।

■ युवाओं को भ्रम और नकारात्मकता से बचाना: यह भी उतना ही महत्वपूर्ण विषय है। युवा ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना केवल परिवार या समाज की जिम्मेदारी नहीं है; सरकार, शिक्षण संस्थानों, मीडिया, उद्योग और सामाजिक संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

युवाओं को किसी भी प्रकार के भ्रम, भ्रामक सूचना, कट्टरता, नशे या ऐसी प्रतियोगियों से बचाने के लिए शिक्षा, तथ्य, संवाद और अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

किसी युवा को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि उस क्या नहीं करना चाहिए।

उसे यह भी दिखाना होगा कि—वह क्या कर सकता है। उसके सामने अवसर होंगे, तो उसकी ऊर्जा निर्माण की दिशा में जाएगी।

आगे की चर्चा...

यह विषय इतना व्यापक है कि इसे एक लेख में समाप्त करना संभव नहीं है। अगले अंक में हम इसी विषय को और आगे बढ़ाएँगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि—

भारत की सरकार, राज्य सरकारें, उद्योग जगत और समाज मिलकर अपने युवा और कार्यशील वर्ग के लिए वास्तव में क्या कर सकते हैं? हम रोजगार से आगे बढ़कर कौशल, उद्यमिता, उद्योग, ग्रामीण युवाओं, विदेशों में रोजगार के अवसर, महिला कार्यबल, नई तकनीक, AI, स्टार्टअप और भविष्य के रोजगार जैसे विषयों पर भी चर्चा करेंगे।

क्योंकि मेरा विश्वास है—

भारत की सबसे बड़ी पूँजी केवल उसकी जनसंख्या नहीं है; उसकी सबसे बड़ी पूँजी उसके युवाओं की ऊर्जा, उत्साह, प्रतिभा, कौशल और आंतरिक शक्ति है।

और इस शक्ति को सही दिशा देना केवल सरकार का नहीं, हम सबका दायित्व है।

आपका अपना, प्रधान संपादक असित पाठक

विशेष लेख

सोशल मीडिया – कमाई, कारोबार और ज्ञान का नया केंद्र



तनय की दृष्टि से...

डिजिटल डेस्क। आज के दौर में सोशल मीडिया की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। एक समय था जब इसका इस्तेमाल सिर्फ दूर बैठे दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन आज यह कमाई, बिज़नेस और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि, **“सोशल मीडिया सिर्फ लोगों से जुड़ने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह कमाई का जरिया भी है। यहाँ विज्ञापन, चीज़ों की खरीद-बिक्री और ज्ञान साझा करने जैसे कई काम होते हैं।”**

बिज़नेस और विज्ञापनों का नया गढ़ छोटे स्टार्टअप्स से लेकर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक, सभी के लिए सोशल मीडिया ग्राहकों तक पहुँचने का सबसे आसान माध्यम बन गया है। आज **“कई लोग अपने बिज़नेस पेज पर पोस्ट या विज्ञापन के जरिए अनेक उत्पाद बेचते हैं।”** ई-कॉमर्स और डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) ब्रांड्स के लिए यह सीधे उपभोक्ताओं से संवाद करने का बेहतरीन जरिया है। लक्षित (Targeted) ऑर्डियंस तक पहुँचने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ **“कंपनियाँ मेरा और गूगल एड्स की मदद से अपने संभावित ग्राहकों तक पहुँचती हैं।”**

हालाँकि, अभी भी एक बड़ा गुर्र इस डिजिटल क्रांति का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। डिजिटल विशेषज्ञों का कहना है

विचार लेख

GeM के 10 साल — भाग 2 : सरकारी बाजार के दरवाजे खुले, लेकिन छोटे कारोबारी के लिए रास्ता कितना आसान?



● प्रदीप सेनी

eM के 10 साल — भाग 3 ऑर्डरपूराहोगया...लेकिनपैसाकबमिलेगा? Delivery से CRAC और Payment तक—Seller के लिए जरूरी जानकारी प्रदीप सेनी

GeM पर Bid जीत गई। सरकारी ऑर्डर मिला। Seller ने सामान खरीदा, पैक किया और समय पर विभाग तक पहुंचा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल—भुगतान कब आएगा? पिछली कड़ी में हमने Startup, MSME, GeM Sahay और TReDS के जरिए छोटे कारोबारियों के लिए खुले अवसरों को समझा था। अब बात उस चरण की, जहां हर Seller की नजर टिकती है—Payment। Delivery के बाद PRC और CRAC सामान पहुंचने के बाद consignee उसकी प्राप्ति दर्ज करता है और PRC—Provisional Receipt Certificate की प्रक्रिया होती है। इसके बाद सामान की जांच कर उसे स्वीकार, आंशिक रूप से स्वीकार या उचित कारण से reject किया जा सकता है। इसके बाद जारी होता है CRAC—Consign-ee Receipt-cum-Acceptance Certificate। सरल भाषा में, CRAC यह बताता है कि विभाग ने कितनी supply स्वीकार की है। यही Payment प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार बनता है।

Payment कितने समय में?

GeM की सामान्य शर्तों के अनुसार CRAC

जारी होने और online bill submit होने के बाद सामान्यतः 10 दिनों के भीतर 100% payment किया जाना चाहिए। हालांकि किसी विशेष Bid की STC या ATC में अलग शर्त हो सकती है। यहां एक बात साफ समझनी चाहिए—इसे “GeM की Payment Guarantee” कहना पूरी तरह सही नहीं है। GeM भुगतान के लिए time-bound contractual framework देता है, लेकिन Buyer की जगह स्वयं पैसा देने वाला guarantor नहीं है।

Buyer देरी करे तो क्या?

यदि CRAC या Payment में अनुचित देरी हो रही है, तो Seller GeM के grievance/incident mechanism और contract में उपलब्ध remedies का उपयोग कर सकता है। इसलिए Seller के लिए सिर्फ delivery करना ही नहीं, बल्कि PRC, CRAC, invoice और payment status को लगातार track करना भी जरूरी है। MSME के लिए अतिरिक्त सुरक्षा पात्र Micro और Small Enterprises को delayed payment के मामलों में MSMED Act के तहत अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। सामान्यतः agreed payment period 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकता। पात्र MSE विवाद की स्थिति में MSME Samadhaan/MSEFC का रास्ता अपना सकता है।

पुराने सरकारी contractual disputes के समाधान के लिए सरकार ने Vivad se Vishwas II जैसी one-time settlement scheme भी चलाई थी, जिसमें GeM portal के माध्यम से eligible claims लिए गए थे।

कुल मिलाकर GeM पर सफलता केवल ऑर्डर मिलने में नहीं है। Seller को De-livery से लेकर PRC, CRAC, Invoice और Payment तक पूरी chain समझनी होगी।

क्योंकि कारोबार में ऑर्डर जीतना पहला कदम है—असल सफलता तब है जब उसका पैसा समय पर खाते में पहुंचे।

अगली कड़ी में—भाग 4

“L1 की दौड़: ऑर्डर जीता या घाटा खरीदार?”

सबसे कम Rate देना हमेशा फायदे का सौदा है या नहीं? Reverse Auction में कितनी नीचे जाए कीमत—अगली कड़ी में समझेंगे इसका पूरा गणित।



नारी शक्ति — परिवार, समाज और राष्ट्र की असली ताकत



रतना पाठक के कलम से...

“यत्र नार्यस्तु

पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलाः क्रियाः॥”

अर्थात् जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास माना जाता है और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए कार्य निष्फल हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को केवल परिवार की एक सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति, सृजन, संस्कार और समृद्धि के आधार के रूप में देखा गया है। माता सीता का धैर्य और मर्यादा, माँ दुर्गा की शक्ति तथा माँ सरस्वती का ज्ञान—नारी के विभिन्न स्वरूपों और

उसकी व्यापक भूमिका को दर्शाते हैं।

नारी शक्ति का वास्तविक अर्थ

नारी शक्ति का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है। इसका अर्थ है—उन्हें सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा, समान अवसर और अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता देना। आज भारतीय नारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा, साहस और परिश्रम के मामले में वह किसी से पीछे नहीं है। शिक्षा से लेकर उद्योग तक, प्रशासन से लेकर राजनीति तक, खेल से लेकर विज्ञान और अंतरिक्ष तक—महिलाएँ निरंतर अपनी पहचान बना रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, कल्पना चावला और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसी अनेक महिलाएँ हमारे सामने इसके प्रेरक उदाहरण हैं।

लेकिन नारी शक्ति की पहचान केवल प्रसिद्ध नामों से नहीं होती। देश के

करोड़ों परिवारों में अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए प्रतिदिन समर्पण के साथ काम करने वाली महिलाएँ भी इस शक्ति का महत्वपूर्ण स्वरूप हैं।

परिवार की पहली शिक्षिका

किसी भी राष्ट्र की नींव उसके परिवारों के बनती है और परिवार में बच्चे की पहली शिक्षिका प्रायः उसकी माँ होती है। एक माँ बच्चे को केवल जीवन जीने की कला नहीं सिखाती, बल्कि संस्कार, अनुशासन, संवेदना, धैर्य और जिम्मेदारी जैसे जीवन-मूल्य भी देती है। यही संस्कार आगे चलकर समाज और राष्ट्र के चरित्र को प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है—

“यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है; लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं।”

इसलिए किसी बेटी की शिक्षा केवल उसके व्यक्तिगत भविष्य में निवेश नहीं है; यह आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में निवेश है। **इतिहास में नारी शक्ति** भारत का इतिहास ऐसी महिलाओं के से बनती है जो नारी के जीवन के उदाहरणों से भरा है जिन्होंने अपने समय की सीमाओं को चुनौती देकर समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस के साथ अंग्रेजों का सामना किया। लोकमता अहिल्यादेवी होलकर ने सुशासन, लोककल्याण और सांस्कृतिक-धार्मिक संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए। देश के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार में उनका योगदान आज भी स्मरण किया जाता है। सावित्रीबाई फुले ने ऐसे समय में

लड़कियों की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जब महिलाओं की शिक्षा के सामने सामाजिक बाधाएँ बहुत बड़ी थीं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जब समाज को परिवर्तन और नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी, तब नारी ने अर्थव्यवस्था, प्रशासन, विज्ञान, उद्योग, राजनीति और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए नारी सशक्तिकरण केवल महिलाओं का विषय नहीं है। यह परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति का विषय है। **नारी—राष्ट्र निर्माण की शक्ति** एक सशक्त महिला अपने जीवन को बदलती है, एक शिक्षित माँ एक परिवार की दिशा बदलती है और अवसर प्राप्त करने वाली महिलाओं की पूरी पीढ़ी समाज की दिशा बदल सकती है। इसलिए भारत के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना नारी की समान भागीदारी के

जिसमें वे अपने सपनों को साकार कर सकें। नारी को केवल परिवार की जिम्मेदारियों के सीमित रखना उसके योगदान को व्यापकता को कम करके देखना होगा। आज वह परिवार के साथ-साथ शिक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, विज्ञान, उद्योग, राजनीति और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए नारी सशक्तिकरण केवल महिलाओं का विषय नहीं है। यह परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति का विषय है। **नारी—राष्ट्र निर्माण की शक्ति**

एक सशक्त महिला अपने जीवन को बदलती है, एक शिक्षित माँ एक परिवार की दिशा बदलती है और अवसर प्राप्त करने वाली महिलाओं की पूरी पीढ़ी समाज की दिशा बदल सकती है। इसलिए भारत के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना नारी की समान भागीदारी के

बिना नहीं की जा सकती।

हमारी संस्कृति ने सदियों पहले नारी को शक्ति का स्वरूप माना था। आज आवश्यकता है कि हम उस विचार को आधुनिक जीवन में सम्मान, समान अवसर, शिक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के रूप में साकार करें।

क्योंकि—

“सशक्त नारी — समर्थ परिवार — समृद्ध समाज — शक्तिशाली राष्ट्र।” और अंत में—

“नारी त्रिभुवनधारा, नारी शक्तिस्वरूपिणी”

अर्थात् नारी जीवन को धारण करने वाली शक्ति है और नारी ही शक्ति के वास्तविक स्वरूप का प्रतीक है। नारी का सम्मान हमारी परंपरा ही नहीं, भारत के उज्ज्वल भविष्य की आवश्यकता भी है।

गोविंदपुरा की 'रिकॉर्ड ब्रेकर' जननेता श्रीमती कृष्णा गौर के राजनीतिक सफर और जन्मदिन पर विशेष

इंदौर के काछी मोहल्ले से शुरू हुआ सफर आज गोविंदपुरा के अजेय दुर्ग तक पहुंच चुका है। विरासत में मिली राजनीति को अपनी मेहनत, सादगी और कड़क प्रशासकीय क्षमता से नया मुकाम देने वाली कृष्णा गौर आज मध्य प्रदेश की राजनीति में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं।



भारतीय राजनीति में यह धारणा आम है कि विरासत में मिली राजनीतिक सत्ता को संभालना आसान होता है, लेकिन उसे अपने दम पर एक नए शिखर तक ले जाना और जनता के बीच अपनी स्वतंत्र व मजबूत पहचान बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस चुनौती को पार कर एक नया कीर्तिमान रचने वाली नेता हैं—श्रीमती कृष्णा गौर।

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, गोविंदपुरा विधानसभा (154) से 'रिकॉर्ड ब्रेकर' विधायक, भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वर्तमान में डॉ. मोहन यादव सरकार में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर 26 सितंबर को अपना जन्मदिवस मना रही हैं।

इंदौर की गलियों से शुरू होकर भोपाल के सत्ता विमर्श तक पहुंचने वाली उनकी यह राजनीतिक यात्रा दृढ़ इच्छाशक्ति, सेवाभाव और असीमित संघर्ष की एक बेहद प्रेरणादायी दास्तान है। छात्र जीवन से ही अंकुरित हो गए थे नेतृत्व के बीज कृष्णा गौर का राजनीति से परिचय अचानक नहीं हुआ। उनका जन्म इंदौर के काछी मोहल्ला में हुआ था।

उनकी राजनीतिक चेतना और नेतृत्व क्षमता की नींव उनके छात्र जीवन में ही पड़ गई थी, जब उन्होंने इंदौर में एम.ए. की पढ़ाई के दौरान अपना पहला छात्र संघ चुनाव लड़ा था। जनता के बीच जाकर उनके मुहों को उठाने की जो कला उन्होंने कॉलेज के दिनों में सीखी, वही बाद में उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनी।

भोपाल के सबसे कड़ावर राजनीतिक परिवार, यानी

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर के परिवार की बहू बनने के बाद, उन्होंने खुद को सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जनसेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया।

प्रशासनिक दक्षता की पहली कसौटी: पर्यटन निगम से लेकर नगर निगम तक

मुख्यधारा की राजनीति और प्रशासन में उनका औपचारिक व सशक्त प्रवेश साल 2005 में हुआ, जब उन्हें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

इस पद पर रहते हुए उन्होंने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचार किए और अपनी कार्यक्षमता का लोहा मनवाया।

इसके बाद भोपाल की जनता ने उन्हें अपना प्रथम नागरिक चुना और वे भोपाल की महापौर बनीं।

महापौर के रूप में उनके कार्यकाल को राजधानी के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, स्वच्छता अभियानों को गति देने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए आज भी याद किया जाता है।

एक महापौर के तौर पर उन्होंने खुद को 'वीआईपी' संस्कृति से दूर रखकर एक जमीनी और संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित किया।

विरासत की चुनौती और 2018 का वो ऐतिहासिक चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति में 'गोविंदपुरा' को दशकों से गौर परिवार और भारतीय जनता पार्टी का अजेय गढ़ माना जाता है।

स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने 1980 से लेकर 2013 तक

जमीन से जुड़ी नेता, जो जनता के बीच रहती हैं

कृष्णा गौर की सबसे बड़ी ताकत उनका आम जनता के लिए सुलभ होना है। वीआईपी कल्चर से कोसों दूर, वे आज भी गोविंदपुरा के हर सुख-दुख में खड़ी नजर आती हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दायित्व के साथ-साथ मंत्री पद का बखूबी निर्वहन करते हुए, वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' के संकल्प को जमीन पर उतार रही हैं।

लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। साल 2018 के विधानसभा चुनावों में जब उम्र और स्वास्थ्य कारणों से बाबूलाल गौर ने सक्रिय चुनावी राजनीति से विभ्राम लिया, तब विपक्ष इसे एक मौके के रूप में देख रहा था।

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इस भारी-भरकम विरासत को सहेजने की जिम्मेदारी कृष्णा गौर को सौंपी। पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरीं कृष्णा गौर ने विरोधियों के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए।

उन्होंने न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की, बल्कि एक नया

इतिहास रचते हुए 'भोपाल के इतिहास में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक' बनने का गौरव भी हासिल किया। यह उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण था कि जनता ने उन्हें केवल बाबूलाल गौर की बहू के रूप में नहीं, बल्कि अपनी 'जनप्रतिनिधि' के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था।

2023 का जनगणना: 1.06 लाख मतों की महाविजय कृष्णा गौर की राजनीतिक ताकत और जनता के दिलों में उनके प्रति अथाह प्रेम का सबसे बड़ा प्रकटीकरण

साल 2023 के विधानसभा चुनावों में हुआ। पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया और इस बार उन्होंने जीत का ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, जिसकी गुंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। गोविंदपुरा सीट से उन्होंने 1 लाख 6 हजार से अधिक मतों के एक विशाल और ऐतिहासिक अंतर से चुनाव जीता। यह जीत इस बात पर पक्की मुहर थी कि अब वे विरासत की छांव से बाहर निकलकर अपने दम पर खड़ी एक कड़ावर 'जननेता' बन चुकी हैं। कड़क प्रशासक और महिला सशक्तिकरण की संवाहक वर्तमान में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य करते हुए कृष्णा गौर की कार्यशैली में एक अलग तरह की ऊर्जा और आक्रामकता देखने को मिल रही है। वे दफ्तर में बैठकर फाइलें निपटाने वाली मंत्री नहीं हैं। प्रभार वाले भेदों और विभागों—विशेषकर पिछड़े वर्ग के छात्रावासों, स्कूलों और आश्रमों—का औचक निरीक्षण करना, बच्चों से सीधे बात करना और अव्यवस्था मिलने पर अधिकारियों की तुरंत जवाबदेही तय करना उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा बन चुका है।



प्रदेश का गौरव

किसान के बेटे ने रचा इतिहास, सीधी के नितिन पटेल ने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में हासिल की 10वीं रैंक

कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद नितिन ने कभी हार नहीं मानी। कई बार पढ़ाई के खर्च को लेकर मन में चिंता आई, लेकिन बड़े भाई के प्रोत्साहन और परिवार के सहयोग ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी

रवि शुक्ला/सीधी: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) 2024 का हाल ही में घोषित परिणामों में सीधी जिले के एक किसान परिवार के बेटे ने शानदार सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया है।

ग्राम पचोखर, तहसील चुरहट निवासी नितिन कुमार पटेल ने समाजशास्त्र से MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में प्रदेशभर में 10वीं रैंक प्राप्त कर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नितिन एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

उनके पिता उदयभान पटेल खेती-किसानी करते हैं, जबकि माता देववती पटेल गृहिणी हैं। परिवार में दो भाई और एक बहन हैं। नितिन सबसे छोटे हैं, जबकि बड़े भाई पवन पटेल प्राइवेट नौकरी करते हैं।

नितिन की इस सफलता के पीछे उनके बड़े भाई पवन पटेल का अहम योगदान रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद पवन पटेल ने अपने छोटे भाई की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और हर कदम पर उनका हाथला बढ़ाया।

प्रारंभिक शिक्षा के बाद बेहतर पढ़ाई के लिए नितिन को भोपाल भेजा गया, जहां उन्होंने लगन और मेहनत से अपनी तैयारी जारी रखी। बाद में दोनों भाई इंदौर में रहकर भी संघर्ष करते रहे, जहां पवन नौकरी करते रहे और नितिन पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुटे रहे।

कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद नितिन ने कभी हार नहीं मानी। कई बार पढ़ाई के खर्च को लेकर मन में चिंता आई, लेकिन बड़े भाई के प्रोत्साहन और परिवार के सहयोग ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने MPPSC की परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की।

अपनी सफलता का श्रेय नितिन ने माता-पिता, बड़े भाई पवन पटेल, भाभी, बहन, मित्रों एवं शुभचिंतकों को दिया। उन्होंने कहा कि परिवार का विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है।

नितिन की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल

है। परिजन, मित्र और ग्रामीण लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं।

लोगों का कहना है कि नितिन की सफलता ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल करने का सपना देखते हैं।

आगे नितिन ने युवाओं से कहा कि सफलता के लिए संसाधनों से अधिक जरूरी निरंतर मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को परिस्थितियों से घबराने के बजाय उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए।

उनकी उपलब्धि से गांव के युवाओं में भी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उत्साह बढ़ा है और कई विद्यार्थी अब उच्च शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।



एशियाई खेल 2026: भारत का समग्र प्रदर्शन



● मयंक आनंद

जापान के आइची-नागोया शहर में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 (19 सितंबर से 4 अक्टूबर) में भारत का अभियान इस समय पूरे जोश में है। भारत का 501 सदस्यीय दल इन खेलों में उतरा है, जो देश की एशियाई खेलों में लगातार 20वीं भागीदारी है।

इस बार 43 खेलों की 469 स्पर्धाओं में कुल पदक दांव पर हैं, और भारत का लक्ष्य 2023 के हांगझोऊ खेलों के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 106 पदक (28 स्वर्ण, 38 रजत, 40 कांस्य) के साथ चौथा स्थान — को पीछे छोड़ना है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अब तक चार स्वर्ण,



13 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 31 पदक जीते हैं, और पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। चीन 186 पदकों (111 स्वर्ण सहित) के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान है।

शुरुआती दिनों का प्रदर्शन

भारत के अभियान की शुरुआत निशानेबाजी से हुई। एलावेनिल वालारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत जीता, फिर सोनम मस्कर और विदर्षा विनोद के साथ टीम स्पर्धा में एक और रजत पदक हासिल किया, जिसमें भारत चीन से पीछे रहा। दूसरे दिन हिमांशु हिल्लों ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में रजत और रुद्राक्ष पाटिल ने कांस्य जीता, फिर दोनों ने पार्थ माने के साथ टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जोड़ा। मिश्रित मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियल ने महिलाओं की पारंपरिक -60 किग्रा स्पर्धा में कांस्य जीतकर भारत को इस खेल में पहला पदक दिलाया।

गोल्डन डबल और क्रिकेट की जीत

तीसरे दिन भारत को धीमी शुरुआत के बावजूद एक बड़ी सफलता मिली — महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 148 रनों के विशाल अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। स्मृति मंधाना ने 45 गेंदों पर 79 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा की तीन विकेट की शानदार गेंदबाजी ने

श्रीलंका को महज 69 रनों पर समेट दिया। इसके बाद कबड्डी में भारत ने इतिहास रचा — महिला टीम ने ईरान को 37-34 से हराकर अपना खिताब बचाया, और कुछ ही देर बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को 40-34 से मात देकर अपना खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा। यह भारत के लिए एक ही दिन में “गोल्डन डबल” था और कबड्डी में भारत के दबदबे को दर्शाता है।

निशानेबाजी में निरंतरता और अन्य खेलों में उम्मीदें शूटिंग में भारत का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा — सुरुचि सिंह और कमलजीत ने मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण जीता। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल और नीरज कुमार ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।

व्यक्तिगत खिलाड़ियों ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन में 1982 के बाद भारत का पहला पदक जीता — अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 21 सेकंड बेहतर करते हुए 2:11:37 के समय के साथ रजत पदक। मुक्केबाजी में अंकुश और परवीन दोनों सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुके हैं, जबकि स्वचैश में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने अपने-अपने फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा भी महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर पदक की उम्मीद जगा रही हैं।

नीरज चोपड़ा की चोट के कारण भाला फेंक में खिताब बचाव से बाहर होने के बावजूद, भारतीय दल में मनु भाकर, लवलीना बोरगोहेन और अमन सेहरावत जैसे कई ओलंपिक पदक विजेता शामिल हैं, जिनसे आगामी दिनों में और पदकों की उम्मीद है। टूर्नामेंट अभी जारी है, और भारत का अंतिम पदक तालिका इन खेलों के अंत तक स्पष्ट होगी।

अन्य खेलों में भारत की उपलब्धियां

पदक तालिका के अलावा, भारत की सफलता कई नए और अप्रत्याशित क्षेत्रों में भी दिखी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किग्रा स्पर्धा में रजत पदक जीतकर 1998 के बैकॉक खेलों के बाद भारोत्तोलन

में भारत का पहला एशियाई खेल पदक हासिल किया — यह 87 किग्रा स्नैच और 111 किग्रा क्लीन एंड जर्क के संयुक्त प्रयास का नतीजा था। वुशु में नाओरेम रोशिवीना देवी ने रजत पदक जीता, जबकि टेबल टेनिस में मनुष थाह और दिव्या चितले की जोड़ी ने मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीतकर इस खेल में भारत का चौथा ऐतिहासिक एशियाई खेल पदक हासिल किया।

निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में भी भारत को सफलता मिली — रायज़ा हिल्लों, परिनाज़ ढालीवाल और महेश्वरी चौहान की महिला टीम, तथा अनंतजीत सिंह नरुका, मिराज अहमद खान और भावतेग सिंह की पुरुष टीम, दोनों ने अपनी-अपनी स्कीट स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते।

एथलेटिक्स ट्रैक पर मजबूत प्रदर्शन

एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहनीय रहा। ताजिंदरपाल सिंह तूर ने पुरुषों की गोला फेंक में रजत जीता, गुनवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया, और सावन बरवाल की मैराथन में ऐतिहासिक रजत के अलावा बारानिका इलांगोवन (पोल वॉल्ट), मनप्रीत कौर (गोला फेंक), सीमा कुमारी और प्राची चौधरी ने ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में कांस्य पदक जोड़े।

इन नतीजों ने पुष्टि की कि भारत का एथलेटिक्स दल, जो 2023 हांगझोऊ खेलों में 29 पदकों (छह स्वर्ण सहित) के साथ सबसे बड़ा पदक स्रोत रहा था, इस बार भी मजबूती से मैदान में

डटा हुआ है।

नए खेलों में पहली सफलताएं

इस संस्करण की खास बात यह रही कि भारत ने कई ऐसे खेलों में पहली बार पदक जीते जहां पहले कभी पदक नहीं मिला था — सॉफ्ट टेनिस में जय मीना, रोडिंग में सतनाम सिंह और सलमान खान, तथा स्वचैश मिश्रित युगल में जोशना चिनप्पा और वेलावन सैथिलकुमार की जोड़ी ने अपने-अपने खेलों में भारत के लिए इतिहास रचा। जोशना चिनप्पा के लिए यह उनका छठा एशियाई खेल पदक रहा, जो 2010 गुआंगझोऊ खेलों से शुरू हुए उनके शानदार करियर को दर्शाता है।

आगे की राह

आइची-नागोया 2026 के सात खेल — तीरंदाजी, हॉकी, सेलिंग, स्वचैश, सर्फिंग, टेनिस और ट्रायथलॉन — 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन कोटा भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे इन स्पर्धाओं में भारत के प्रदर्शन का महत्व और बढ़ जाता है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से महिला एकल में पदक की उम्मीदें बनी हुई हैं, जबकि मुक्केबाजी में अंकुश और परवीन के सेमीफाइनल प्रदर्शन ने दो और पदक सुनिश्चित कर दिए हैं। टूर्नामेंट के समापन तक कुछ और दिन शेष हैं, और भारतीय दल का लक्ष्य 2023 के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पार करना है।



मनोरंजनम्

सात दशकों में पहली बार दिल्ली से बाहर निकले

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, गुजरात में सजी सिनेमा की

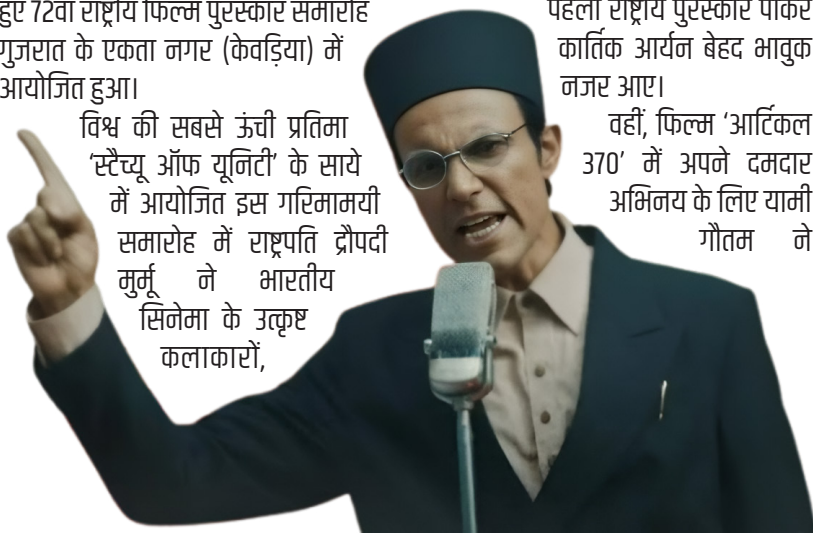
केवड़िया में राष्ट्रपति ने किया सितारों का सम्मान; कार्तिक आर्यन और ममूटी बने सर्वश्रेष्ठ

अभिनेता, मनोज मुंतशिर को मिला गीतकार का पुरस्कार



मुंबई। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार’ के पन्नों में इस बार एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। पुरस्कारों के सात दशक लंबे इतिहास में यह पहला मौका है, जब यह भव्य समारोह देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है। स्थापना के बाद से अब तक यह आयोजन हमेशा दिल्ली के विज्ञान भवन में ही होता आया था, लेकिन इस बार परंपरा को बदलते हुए 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में आयोजित हुआ।

विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के साये में आयोजित इस गरिमामयी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट कलाकारों,



निर्देशकों और पदों के पीछे काम करने वाले हुनरमंदों को सम्मानित किया।

इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार युवा कलाकार कार्तिक आर्यन और मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। कार्तिक को यह सम्मान उनकी फिल्म ‘चंद्र चैंपियन’ में शानदार अभिनय के लिए मिला, जबकि ममूटी को यह पुरस्कार उनकी फिल्म ‘ब्रह्मयुगम’ के लिए दिया गया। अपना

पहला राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर कार्तिक आर्यन बेहद भावुक नजर आए।

वहीं, फिल्म ‘आर्टिकल 370’ में अपने दमदार अभिनय के लिए यामी गौतम ने

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने नाम किया।

मुख्य फिल्मों (फीचर फिल्म) की श्रेणी में इस बार ‘आर्टिकल 370’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार मिला।

वहीं, दृष्टिहीन उद्योगपति श्रीकांत बोला के जीवन पर आधारित राजकुमार राव अभिनीत फिल्म ‘श्रीकांत’ को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुना गया। प्रभास और अमिताभ बच्चन की भव्य फिल्म ‘काल्हि 2898 एडी’ को ‘संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म’ का पुरस्कार मिला।

संगीत और गीत लेखन की दुनिया में जाने-माने गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक बार फिर अपनी कलम का जादू बिखेरा है।

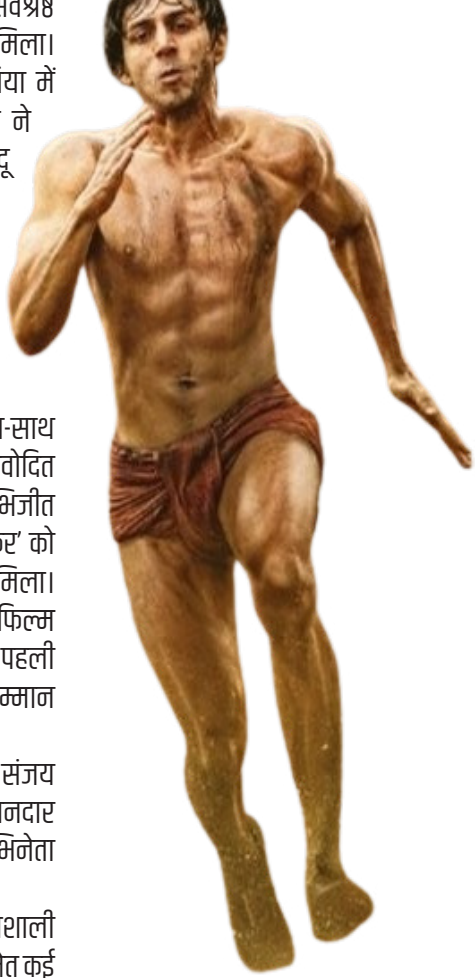
उन्हें अभिनेता अजय देवगन की फिल्म ‘मैदान के भावुक कर देने वाले गीत ‘जाने दो’ के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

समारोह में बड़ी फिल्मों के साथ-साथ लघु फिल्मों (शॉर्ट फिल्म) और नवोदित प्रतिभाओं को भी खूब सराहा गया। अभिजीत अरविंद दळवी द्वारा निर्देशित ‘हमसफर’ को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार मिला। वहीं, अभिनेता रणदीप हुड्डा को उनकी फिल्म ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ के लिए पहली फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान दिया गया।

इसके अलावा, दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा को फिल्म ‘भक्षक’ में उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला।

इस भव्य आयोजन का सबसे गौरवशाली पल वह रहा, जब कन्नड़ और हिंदी समेत कई

भाषाओं की 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके वयोवृद्ध अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान ‘दादा साहेब फाल्के पुरस्कार’ से नवाजा गया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिनेमा के व्यापक प्रभाव का जिक्र किया और सभी कलाकारों से अपील की कि वे अपनी लोकप्रियता का उपयोग समाज में सकारात्मकता और जागरूकता फैलाने के लिए करें।



द पैराडाइज का बॉक्स ऑफिस पर धमाल

3 दिन में पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा,

जारी है नानी की फिल्म की रफ्तार



● हिमांशु मिश्रा

नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नानी की फिल्म ‘द पैराडाइज’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए तीन दिन बीत चुके हैं और इसी के साथ इसने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती दिनों में समीक्षकों की ओर से मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, जिससे इसकी कमाई लगातार बढ़ रही है।

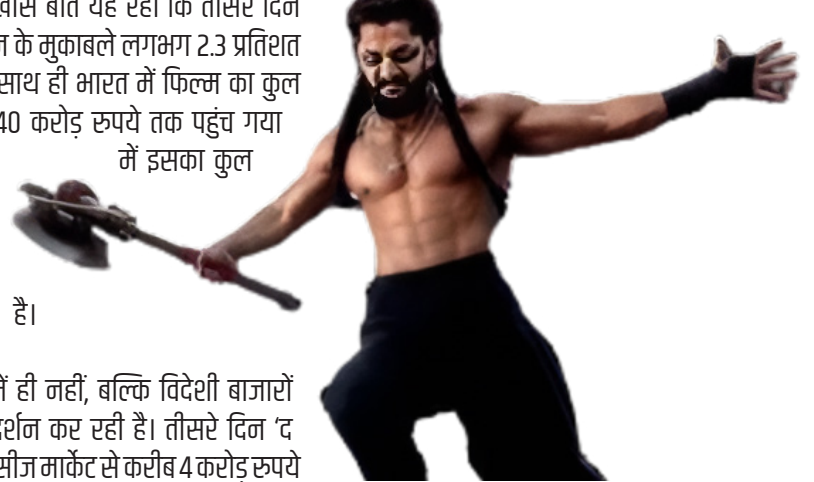
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन यानी शनिवार को भारत में करीब 15.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। खास बात यह रही कि तीसरे दिन की कमाई दूसरे दिन के मुकाबले लगभग 2.3 प्रतिशत ज्यादा रही। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 76.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि भारत में इसका कुल ग्राँस कलेक्शन करीब 90.50 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

फिल्म सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। तीसरे दिन ‘द पैराडाइज’ ने ओवरसीज मार्केट से करीब 4 करोड़ रुपये

की कमाई की। इसके साथ ही विदेशों में फिल्म का कुल ग्राँस कलेक्शन लगभग 29 करोड़ रुपये हो गया है।

भारत और विदेशी बाजारों की कमाई को मिला दें, तो फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्राँस कलेक्शन अब तक करीब 119.50 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है। यानी महज तीन दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का बड़ा आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है।

बता दें कि ‘द पैराडाइज’ में नानी के साथ राघव गुजाल भी एक अहम और दमदार भूमिका में नजर आ रहे हैं। पेन-इंडिया स्तर पर रिलीज हुई यह एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है। शुरुआती तीन दिनों के शानदार प्रदर्शन के बाद अब फिल्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाले कार्यदिवसों (Weekdays) में कमाई की इस रफ्तार को कायम रखने की होगी।



रुस का “शैडो फ्लीट” — वह प्रतिबंध-भेदी तंत्र जो लगातार बढ़ता जा रहा है

● अंजली सिंह

यूक्रेन युद्ध के बाद रुसी तेल पर पश्चिमी प्रतिबंध लागू हुए करीब चार साल बीत चुके हैं, लेकिन शिपिंग रिकॉर्ड और प्रतिबंध संबंधी आंकड़ों की एक गहन जांच से पता चलता है कि एक विशाल और गुप्त समुद्री नेटवर्क अब भी प्रवर्तन एजेंसियों को चकमा देने में सफल हो रहा है।

अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रतिबंधित टैंकर रुस के कच्चे तेल के निर्यात का 61% और कुल समुद्री तेल शिपमेंट का 52% हो रहे थे — यह साफ दर्शाता है कि यह “शैडो फ्लीट” अब कोई मामूली बचाव का रास्ता नहीं, बल्कि रुस के तेल निर्यात का मुख्य आधार बन चुका है। इस अभियान का पैमाना चौकाने वाला है।

यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने फरवरी 2026 तक 1,337 जहाजों को इस शैडो फ्लीट का हिस्सा बताते हुए सूचीबद्ध किया है, जबकि समुद्री खुफिया फर्म विंडवर्ड के अनुसार व्यापक “डार्क फ्लीट” में 1,000 से अधिक ऐसे जहाज शामिल हैं जो अनियमित



ध्वज परिवर्तन, अस्पष्ट स्वामित्व और अपने पहचान संकेतों (AIS) में छेड़छाड़ के जरिए अपनी गतिविधियां छिपाते हैं।

ये जहाज आमतौर पर पुराने और खस्ताहाल हालत में होते हैं — शैडो फ्लीट के जहाजों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि नियमित टैंकरों की मात्र 9 वर्ष, जिससे पर्यावरणीय आपदा का गंभीर खतरा पैदा होता है।

यूरोप में जबी अभियान बनाम कानूनी अड़चनें

यूरोपीय देशों ने हाल के महीनों में इन जहाजों को पकड़ने के प्रयास तेज किए हैं। ब्रिटेन ने जून 2026 में अंग्रेजी चैनल में “स्मिर्टोस” नामक जहाज को हिरासत में लिया — जिसे ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला ऑपरेशन बताया।

इसी तरह फरवरी 2026 में स्वीडिश तटरक्षक बल ने बाल्टिक सागर में “**किवाला**” नामक पलाऊ-ध्वज वाले टैंकर को रोका,

जो 23,000 मीट्रिक टन रुसी कच्चा तेल ले जा रहा था और जिसका बीमा प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया।

लेकिन जांच से यह भी पता चलता है कि कानूनी ढांचा अब भी कमजोर है। मौजूदा ब्रिटिश और यूरोपीय संघ के कानूनों के तहत, अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में विदेशी ध्वज वाले जहाज केवल प्रतिबंधित माल ढोने भर से स्वतः अपराधी नहीं माने जाते। 2024 और 2025 में यूरोप में जब्त किए गए हर जहाज को माल सहित छोड़ दिया गया, हालांकि कुछ मामलों में आपराधिक जांच जारी रही।

चीन और भारत जैसे बाजारों की भूमिका

अमेरिकी कांग्रेस की चीन संबंधी सिलेक्ट कमेटी की मार्च 2026 की एक रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ कि चीन शेल कंपनियों, चीनी रिफाइनरियों और शैडो फ्लीट टैंकरों के जरिए ईरान, रुस और वेनेजुएला से भारी छूट पर

करोड़ों बैरल तेल खरीद रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि जब तक चीन, भारत, तुर्की और मलेशिया जैसे बड़े बाजार इस तेल को खरीदते रहेंगे, तब तक यह अवसर की खिड़की खुली रहेगी। चीनी और भारतीय बैंकों पर बड़े पैमाने पर द्वितीयक प्रतिबंध ही एकमात्र प्रभावी उपाय माना जा रहा है, लेकिन इसकी भू-राजनीतिक कीमत — व्यापारिक जवाबी कार्रवाई और डॉलर की आरक्षित मुद्रा स्थिति पर दबाव — अब तक किसी भी सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति से अधिक भारी साबित हुई है। यह अंतर — प्रतिबंधों की बढ़ती संख्या और तेल व्यापार में शैडो फ्लीट की स्थिर होती पकड़ के बीच — इस पूरी जांच का केंद्रीय सवाल है, जो दिखाता है कि कागज पर सख्त होते प्रतिबंध जमीनी स्तर पर कितनी आसानी से बेअसर साबित हो सकते हैं।

दो हजार साल बाद रोशनी में आया प्राचीन रोम का सबसे बड़ा भित्ति-चित्र

● वैभव भट्ट

दिल्ली। रोम के अधिकारियों ने 8 सितंबर, 2026 को एक असाधारण खोज को जनता के सामने पेश किया — प्राचीन रोम का अब तक ज्ञात सबसे बड़ा भित्ति-चित्र (फ्रैस्को) और मोजेक परिसर, जो लगभग तीन दशक पहले खोजे जाने के बाद अब पहली बार आम लोगों के देखने के लिए खोला गया है।

यह पहली शताब्दी ईस्वी का “पेट्रेड सिटी” नामक भित्ति-चित्र और उससे जुड़ा “ग्रेट मोजेक” कोलोसियम के पास ओपियो पहाड़ी पर स्थित ट्रोजन के स्नानागार (बायस ऑफ ट्रोजन) की खुदाई के दौरान **1990 के दशक में एक भूमिगत गैलरी में मिला था** — जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्नानागार परिसर हुआ करता था। रोम के मेयर रॉबर्टो गुआल्टिएरी ने इस हाल ही में पुनर्स्थापित कलाकृति का अनावरण करते हुए बताया कि यह प्राचीन रोम की अपनी तरह की सबसे बड़ी दीवार-कला है।

यह भित्ति-चित्र एक चारदीवारी वाले बंदरगाह शहर को ऊपर से देखे गए दृश्य (बर्ड्स-आई व्यू) के रूप में दर्शाता है — जिसमें इमारतें, एक थिएटर, एक मंदिर, सार्वजनिक चौक और मीनारें साफ नज़र आती हैं। सदियों तक भूमिगत छिपे रहने के बावजूद इसके नीले और टैराकोटा रंग आज भी स्पष्ट हैं, हालांकि समय के साथ कुछ फीके पड़ गए हैं।

मेयर गुआल्टिएरी ने इसे कला और इतिहास दोनों दृष्टियों से “दुनिया में वाकई अनूठा” बताया।



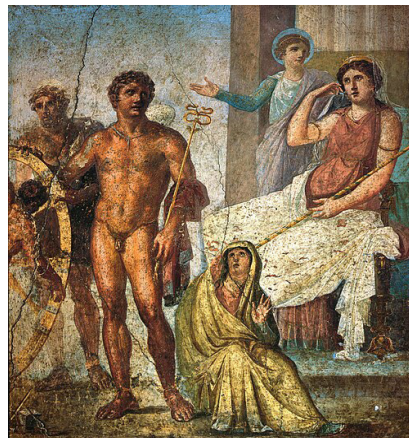
“हम नहीं जानते कि यह किस शहर से जुड़ा है, लेकिन वह ज़रूर कोई बेहद प्रसिद्ध शहर रहा होगा,” उन्होंने कहा।

मेयर गुआल्टिएरी



रोम की सांस्कृतिक अधीक्षक क्लाउडियो पारीसी प्रेसीचे ने कहा कि इस बंदरगाह शहर की भव्यता — जिसमें इमारतें, थिएटर, मंदिर, सार्वजनिक चौक और मीनारें शामिल हैं — बेहद अच्छी तरह संरक्षित पाई गई है, हालांकि यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि यह चित्र वास्तव में किस शहर को दर्शाता है।

करीब 15 मीटर ऊंचा यह मोजेक भी भारीकी से सजाए गए स्तंभों, वास्तुशिल्प तत्वों और चार अलग-अलग स्तरों पर बनी आकृतियों से सुसज्जित है। पुनर्स्थापन कार्य में सतह पर जमी परतों को हटाना, जोड़ाई को मजबूत करना और दृश्यता बेहतर बनाने की तकनीकें शामिल थीं, ताकि इन नाज़ुक कलाकृतियों की मूल सुंदरता बरकरार रखी जा सके। फिलहाल यह स्थल शुरुआती दौर में सप्ताहांत के दौरान केवल 15 लोगों के छोटे समूहों में ही खोला जा रहा है। इसका उद्देश्य यह परखना है कि बढ़ती नमी और मौसमी बदलावों का



वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े उलटफेर की आहट

सोने में ‘महा-रैली’ के संकेत: **3.5 लाख रुपये (10,000 डॉलर)** तक जा सकता है भाव जेफरीज की रिपोर्ट और अर्थशास्त्रियों का दावा— अमेरिकी डॉलर की कमजोरी, भारी कर्ज और युद्ध के हालात से **सोने-चांदी में आग्री ऐतिहासिक तेजी**; पोर्टफोलियो में गोल्ड का हिस्सा बढ़ाने की सलाह

नई दिल्ली। दुनिया भर के शेयर बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं पर मंडराते संकट के बीच सोने (Gold) में एक ऐतिहासिक उछाल की रूपरेखा तैयार हो रही है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म ‘जेफरीज’ (Jefferies) की रिपोर्ट और शीर्ष अर्थशास्त्रियों के ताजा विश्लेषण ने निवेश जगत में हलचल मचा दी है। अनुमान जताया जा रहा है कि लंबी अवधि में सोना 10,000 डॉलर (लगभग 3.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) प्रति औंस के जादुई और अब तक के सबसे उच्चतम स्तर को छू सकता है।

इस संभावित ‘महा-उछाल’ का सबसे बड़ा कारण अमेरिका का भारी-भरकम कर्ज और डॉलर की कमजोरी को माना जा रहा है। डॉलर का गिरता वर्चस्व और अमेरिका का कर्ज वरिष्ठ अर्थशास्त्री शरद कोहली के अनुसार, अमेरिका इस समय 40 ट्रिलियन डॉलर के अप्रत्याशित कर्ज तले दबा है।

अमेरिकी सरकार के लिए बॉन्ड यील्ड (कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज) को नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। जेफरीज के चीफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफिसर क्रिस वुड का मानना है कि यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बॉन्ड यील्ड को जबरन नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो उसे बाजार में भारी मात्रा में डॉलर छापने पड़ेगा। डॉलर की सप्लाई बढ़ने से उसकी कीमत गिरेगी।

अर्थशास्त्र का यह स्थापित नियम है कि डॉलर जितना कमजोर होता है, सोने की कीमतें उतनी ही तेज गति से ऊपर भागती हैं। केंद्रीय बैंकों की जमाखोरी ने बढ़ाई चिंता बाजार में सोने की कमी का एक बड़ा कारण दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का आक्रामक रुख है। चीन (PBOC), रुस और ब्रिक्स देश डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए (डी-डॉलराइजेशन) लगातार अपना विदेशी मुद्रा भंडार बेचकर फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं।

इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्रीय

बैंक इतने बड़े पैमाने पर सोने की जमाखोरी कर रहे हैं। इसके साथ ही, रुस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के तनाव ने सोने की ‘सेफ हेवन’ (सुरक्षित निवेश) मांग को चरम पर पहुंचा दिया है। **चांदी भी लगाएगी लंबी छलांग**: 200 डॉलर कालक्षय इस तेजी में चांदी (Silver) भी पीछे नहीं रहने वाली है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि चांदी जल्द ही 150 से 200 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंच सकती है। चांदी की मांग केवल आभूषणों तक सीमित नहीं है; इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV), हार्ड-स्पीड ब्रेटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डेटा सेंटरों में चांदी के व्यापक इस्तेमाल के कारण इंडस्ट्री में इसकी भारी शॉर्टेज हो गई है। सट्टेबाजों को अब बाजार में डिलीवरी देने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

निवेशकों के लिए क्या है सबक?

विशेषज्ञों ने साफ किया है कि यह रातों-रात होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक आर्थिक चक्रवात की शुरुआत है। ऐसे में निवेशकों को ‘खरीदो और भूल जाओ’ की पुरानी रणनीति छोड़कर हर तीन महीने में अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करने की सलाह दी गई है। आर्थिक सुनामी की स्थिति में शेयर बाजार टिक नहीं पाएंगे, इसलिए जानकारों का मानना है कि सुरक्षित भविष्य के लिए निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा बढ़ाकर 40 से 50 फीसदी तक करने पर विचार करना चाहिए।

एक नजर में मुख्य कारण:

- ऋण संकट: अमेरिका पर 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, डॉलर के अवमूल्यन का खतरा।
- पेपर बनाम फिजिकल: दुनिया भर के एक्सचेंजों पर मौजूद फिजिकल सोने से 100 गुना ज्यादा सट्टेबाजी के कॉन्ट्रैक्ट्स का होना।
- नई तकनीक: एआई और इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण चांदी की औद्योगिक मांग में रिकॉर्ड इजाफा।

व्यापार:-व्यवसाय:

28-30 सितंबर बैंक हड़ताल: ज़रूरी काम पहले निपटाएं

● कार्तिका गोठवाल

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुराने ज़माने के निजी बैंकों ने ग्राहकों को चेतावनी जारी कर सलाह दी है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने ज़रूरी बैंकिंग काम समय रहते ही निपटा लें। दरअसल, बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 28 सितंबर से तीन दिनों की हड़ताल का आह्वान किया है। लगभग 90 प्रतिशत बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) ने हफ्ते में 5 दिन काम (5-Day Work Week) और अन्य मांगों को लेकर 28 सितंबर से 3 दिनों की हड़ताल की घोषणा की है। अगर यह हड़ताल होती है, तो यह बैंकों के छमाही क्लोजिंग (Half-year-

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के 3 फेज



फेज-1

11 सितंबर को 1 दिन की सरुव्यापी हड़ताल हुई थी।



फेज-2

28 सितंबर से 30 सितंबर तक 3 दिन की हड़ताल।



फेज-3

26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल।



ly Closing) के समय ही पड़ेगी।

तीन दिनों की इस देशव्यापी हड़ताल से पहले ग्राहकों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रविवार, 27 सितंबर को भी शाखाएं खुली रखने के निर्देश दिए हैं।

स्ट्रेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि बैंक अपनी शाखाओं और कार्यालयों में सेवाएं चालू रखने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हड़ताल के दौरान कुछ सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए ग्राहकों से अपील है कि वे पेशानी से बचने के लिए अपने ज़रूरी काम हड़ताल से पहले ही निपटा लें। साथ ही, नकदी के लिए एटीएम और बाकी कामों के लिए योनो (YONO), इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करें।

वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों को संदेश भेजकर अनुरोध किया है कि 28, 29 और 30 सितंबर को होने वाली हड़ताल के दौरान बैंकिंग ज़रूरतों के लिए 24 घंटे उपलब्ध डिजिटल सेवाओं (एटीएम, यूपीआई, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग) की मदद लें।

इस हड़ताल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) भी हिस्सा ले रहे हैं

पुराने निजी क्षेत्र के कर्नाटक बैंक ने बताया कि अगर हड़ताल होती है, तो बैंक की शाखाओं का कामकाज प्रभावित हो सकता है, हालांकि इसे सामान्य बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बैंक के मुताबिक, हड़ताल से होने वाले नुकसान या असर का सीटीक अंदाजा फिलहाल नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी,

एक्सिस और इंडसइंड जैसे नए जमाने के निजी बैंकों में कामकाज सामान्य दिनों की तरह ही चलता रहेगा।

इससे पहले वित्त मंत्रालय ने भी बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की अपील की थी। सरकार का कहना है कि यूनियनों की ज्यादातर मांगों का समाधान पहले ही किया जा चुका है।

यूएफबीयू की अन्य प्रमुख मांगों में पेंशन में सुधार व अपडेट, सभी पेंशनभोगियों के लिए एक समान महंगाई भत्ता (DA) फॉर्मूला, और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का विकल्प देना शामिल है।

सपनों की कोई उम्र नहीं: मातृत्व से लेकर प्रतिष्ठित ‘डीबी मॉल’ की ब्रांड प्रतिनिधि बनने तक मधुलिका वाजपेई की बेमिसाल उड़ान



● प्रकाश त्रिपाठी

समाज में अक्सर यह मान लिया जाता है कि विवाह और मातृत्व के बाद एक महिला के सपनों की उड़ान थम जाती है और उसकी दुनिया केवल घर-परिवार की चौखट तक सीमित रह जाती है। लेकिन, राजधानी भोपाल की मधुलिका वाजपेई ने अपनी मेहनत और लगन से इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है।

‘देश दर्पण संवाद’ के विशेष स्त्री-विमर्श पृष्ठ ‘स्त्री रत्नम’ की इस बार की हमारी विशेष मेहमान मधुलिका वाजपेई हैं। एक पत्नी और एक बच्चे की माँ होने की पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए उन्होंने अपने लिए एक स्वतंत्र और सशक्त रास्ता चुना।

आज वे एक सफल डिजिटल सामग्री रचनाकार, सोशल मीडिया प्रभावक (इन्फ्लुएंसर), मॉडल और शहर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र ‘डीबी मॉल’ की ब्रांड प्रतिनिधि के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं।

इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल मंच पर वे साढ़े सत्रह हज़ार (17.5K) से अधिक अनुयायियों के साथ एक ‘पुरुस्कृत रचनाकार’ और कार्यक्रम आयोजक के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

उनके इसी प्रेरक सफर, संघर्षों और भविष्य के लक्ष्यों को लेकर कार्यकारी संपादक प्रकाश त्रिपाठी ने उनसे एक बेहद स्वास और विचारोत्तेजक बातचीत की।

जिम्मेदारियों के बीच जगती अपनी पहचान की चाह..

अपनी इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत का जिक्र करते हुए मधुलिका बताती हैं कि उनका सफर आम ढर्रे से थोड़ा अलग रहा है। विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक समय ऐसा आया जब उन्हें गहराई से महसूस हुआ कि अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। उनके लिए डिजिटल सामग्री निर्माण का क्षेत्र बिल्कुल नया था, लेकिन उन्होंने अपने जीवंत अनुभवों और रचनात्मकता को एक नए नजरिए से लोगों तक पहुंचाने का दृढ़ निर्णय लिया। यहीं से उनकी इस पेशेवर यात्रा का आरंभ हुआ।

इस पूरी वैचारिक और पेशेवर यात्रा में भोपाल शहर ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई है। मधुलिका का मानना है कि भोपाल उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उनकी पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। वे मानती हैं कि यहाँ की सादगी, अपनापन और सुकून ने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा और अपने काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने की हिम्मत दी।

महिलाओं के लिए उपलब्ध अवसरों पर वे बेबाकी से कहती हैं कि आज भोपाल में अवसर निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, हालांकि जमीनी स्तर पर कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि यदि सही सहयोग और मंच मिले, तो एक महिला अपनी पहचान ख़ुद तय कर सकती है।

आत्म-संदेह से सफलता तक परिवार बना ढाल

एक बिल्कुल नए कार्यक्षेत्र में कदम रखना कभी आसान नहीं होता। नई चीज़ें सीखने के

दौरान मधुलिका के मन में भी कई बार आत्म-संदेह पैदा होता था। लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा एक बात याद दिलाई कि अगर किसी काम की शुरुआत की है, तो खुद को समय भी देना होगा। एक महिला और माँ के रूप में अपनी अलग पेशेवर पहचान बनाने के इस कठिन संघर्ष में उनके परिवार का अटूट समर्थन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा।

मधुलिका गर्व के साथ स्वीकार करती हैं कि परिवार के विश्वास ने ही उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ने का हौसला दिया। जब बात कामकाजी महिलाओं के जीवन में व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन की आती है, तो वे बड़ी स्पष्टता से मानती हैं कि एक ‘आदर्श संतुलन’ हमेशा संभव नहीं होता।

काम और परिवार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वे अपनी प्राथमिकताओं को समझकर कदम बढ़ाती हैं। वे परिवार और काम को साथ लेकर चलने के अलावा स्वयं के लिए एकांत का समय निकालना भी नहीं भूलतीं, जो उन्हें मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखता है।

व्यावसायिक जुड़ाव और भरोसे का प्रतीक

वर्तमान में मधुलिका रचनात्मक सामग्री निर्माण, उपभोक्ता-निर्मित सामग्री, विभिन्न व्यावसायिक उत्पादों के प्रचार और कार्यक्रमों से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं पर पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रही हैं।

अलग-अलग प्रतिष्ठित संस्थानों और स्थानीय कार्यक्रमों के साथ जुड़कर वे दर्शकों तक लगातार कुछ नया और रचनात्मक पहुंचा रही हैं। इसी अथक परिश्रम का परिणाम है कि वे शहर के प्रतिष्ठित डीबी मॉल की प्रचार प्रतिनिधि चुनी गई हैं। मधुलिका इसे अब तक का अपना सबसे बड़ा अवसर और उपलब्धि मानती हैं।

उनके लिए यह केवल एक पदवी नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत पर जताए गए भरोसे और सम्मान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अपने काम के दौरान आने वाली दैनिक चुनौतियों को वे किसी दबाव की तरह नहीं, बल्कि कुछ

नया सीखने के अवसर की तरह देखती हैं।

सपनों की उड़ान के लिए सही समय का इंतजार न करें..

अपने काम के जरिए समाज में आए सकारात्मक बदलाव को वे अपनी सबसे बड़ी कमाई मानती हैं।

जब कोई अन्य महिला उनकी यात्रा से प्रेरित होकर अपनी पहचान बनाने की बात कहती है, तो मधुलिका को लगता है कि उनकी मेहनत सार्थक हो गई।

जो युवा महिलाएं अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए मधुलिका की सलाह बेहद स्पष्ट और व्यावहारिक है। वे कहती हैं कि किसी आदर्श समय का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए; छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए और सीखते हुए आगे बढ़िए।

उनका मानना है कि शुरुआत में लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि कुछ साल बाद आप खुद से क्या कहेंगे।

भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए मधुलिका बताती हैं कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान अपने रचनात्मक कार्य और व्यक्तिगत पहचान को और अधिक मजबूत करने पर है। वे आगे बड़े संस्थानों और अर्थपूर्ण परियोजनाओं के साथ काम करना चाहती हैं, ताकि उनका डिजिटल मंच केवल प्रचार तक सीमित न रहे, बल्कि वहां लोगों से उनके वास्तविक अनुभव भी जुड़ें।

अंत में, ‘देश दर्पण संवाद’ की महिला पाठकों को एक बेहद सशक्त संदेश देते हुए वे कहती हैं, “अपनी पहचान को कभी पीछे मत रखिए। जिम्मेदारियाँ हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए थोड़ा वक निकालना भी तउना ही जरूरी है।

शुरुआत छोटी हो सकती है, उसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखती हैं, तो अपनी नई पहचान बनाने की कोई उम्र नहीं होती।”

रूढ़ियों को तोड़ बॉलीवुड तक उड़ान: 40 लाख दिलों पर राज कर रहीं ‘मधु एसडी किंग’ (रंजना सिंह)

● शिवम शुक्ला

मध्य प्रदेश के सीधी जिले की माटी में पली-बढ़ी एक साधारण सी लड़की ने आज मायानगरी से लेकर डिजिटल दुनिया तक में असाधारण मुकाम हासिल कर लिया है। छोटे से शहर से निकलकर आसमान की बुलंदियों को छूने वाली सीधी की इस होनहार बेटी का नाम है— **मधु एसडी किंग (रंजना सिंह)**।

विध्य क्षेत्र के इस छोटे से जिले से शुरू हुआ उनका सफर आज बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारों तक पहुँच चुका है और वह छोटे शहर के युवाओं के लिए एक जीती-जागती मिसाल बन गई हैं।

शिंभा और कला को अक्सर एक-दूसरे का विरोधी माना जाता है, लेकिन मधु ने इस धारणा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वह बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहने वाली एक अत्यंत प्रतिभावान छात्रा रही हैं।

वर्ष 2026 में, उन्होंने साइंस स्ट्रीम से अपनी 12वीं की परीक्षा में असाधारण और शीर्ष अंक प्राप्त कर अपनी शैक्षणिक प्रतिभा को साबित किया। वहीं दूसरी ओर, उनका सांस्कृतिक और कलात्मक सफर महज चौथी कक्षा की कोमल उम्र में शुरू हो चुका था।

और अब उनका 4 मिलियन **(40 लाख+)** सब्सक्राइबर्स का विशाल परिवार है।

डिजिटल जगत में तहलका:

मधु एसडी किंग ने बॉलीवुड के 30 से अधिक दिग्गजों के साथ किया ग्रैंड कोलैबोरेशन सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी स्वास पहचान बना चुके मधु एसडी किंग ने एक नया इतिहास रच दिया है।

उन्होंने बॉलीवुड और त्सूजिक इंडस्ट्री के 30 से भी ज्यादा बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन कर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा दी है। इस मेगा-कोलैबोरेशन की लिस्ट में बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, अपनी सुरीली आवाज से सभी को दीवाना बनाने वाली सिंगर कनिका कपूर,

युवाओं की पसंदीदा एक्ट्रेस कशिका कपूर, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की वचीन ऐणुका पंवार और बॉलीवुड के ‘बैड मैन्’ गुलशन ग्रोवर जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं।

इनके अलावा भी इंडस्ट्री की कई नामचीन हस्तियों के साथ मधु एसडी किंग के प्रोजेक्ट्स सामने आ चुके हैं।

पिता का संघर्ष: सामाजिक बंदिशों पर विजय मधु के जीवन में उनके पिता स्व. रविराज सिंह एक विशाल बरगद के वृक्ष की तरह रहे, जिसने हर सामाजिक तूफान से अपनी बेटी को बचाकर रखा। जब एक संकुचित मानसिकता वाले समाज ने बेटी के डांस पर सवाल उठाए, तो स्व.रविराज सिंह जी ने समाज की हर बंदिश से अकेला मुकाबला किया।

गुरु ‘एसडी किंग’: कला के शिल्पी और जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक !

कहते हैं कि कच्ची माटी को एक सुंदर मूर्ति में ढालने का काम केवल एक सच्चा गुरु ही कर सकता है। मधु के जीवन में वह मार्गदर्शक बनकर आए उनके डांस टीचर और गुरु सुमित भारती (एसडी किंग)।

गुरु सुमित भारती (एसडी किंग) ने केवल मधु को नृत्य की बारीकियाँ और स्टेज प्रेजेंस ही नहीं सिखाई, बल्कि जीवन में आने वाली हर छोटी-बड़ी मानसिक और व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना भी सिखाया।



विविध संवाद:

‘ब्लड मैन्’ निरीक्षक अनुराग झारिया

‘रक्तदान-महादान’ की अलख जगा रहे मध्यप्रदेश पुलिस के ‘ब्लड मैन्’ निरीक्षक अनुराग झारिया का नलखेड़ा में भव्य सम्मान।



देश दर्पण संवाद/ शिवम शुक्ला

भोपाल- मां बंगलानुखी की पावन धरा नलखेड़ा, जिला अगर मालवा में बीते दिनों एक अत्यंत प्रेरणादायी और गौरवशाली सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में अपने मानवीय कार्यों के चलते ‘ब्लड मैन्’ के रूप में विख्यात हो चुके निरीक्षक अनुराग झारिया का स्थानीय रक्तवीरों एवं समाजसेवियों द्वारा अत्यंत आत्मीय सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम समाज में उनके द्वारा किए जा रहे निस्वार्थ सेवा कार्यों को एक कृतज्ञ श्रद्धांजलि थी।

स्मृति चिन्ह भेंट कर दी गई सेवाओं को दी गई सलामी आयोजित सम्मान समारोह के दौरान स्थानीय रक्तवीरों ने एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर निरीक्षक अनुराग झारिया का सम्मान किया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई समाजसेवी, नियमित रक्तदाता और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे थे। जन-जन तक ‘रक्तदान - महादान’ का पवित्र संदेश पहुंचाने वाले अनुराग

झारिया के इस सम्मान समारोह में उपस्थित रक्तवीरों और आम जनता के बीच भारी उत्साह का माहौल देखा गया।

जीवन रक्षक प्रयासों की हुई चौतरफा सराहना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित वक्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने रक्तदान एवं समाजसेवा के क्षेत्र में निरीक्षक अनुराग झारिया के उल्लेखनीय योगदान की जमकर सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान के प्रति आम जनमानस में जागरूकता बढ़ाने और आपात स्थिति में जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयास न केवल प्रशंसनीय हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी भी हैं।

सच्ची सेवा का दिया मूलमंत्र

सम्मान से अभिभूत निरीक्षक अनुराग झारिया ने इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि, “रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना और जरूरतमंदों तक समय पर रक्त पहुंचाना ही सच्ची सेवा

है।” उनका यह कथन उनके जीवन दर्शन और समाज के प्रति उनके समर्पण को भली-भांति दर्शाता है।

पुलिस की छवि को मिली नई ऊँचाई

इस अवसर पर स्थानीय रक्तवीरों ने निरीक्षक झारिया के प्रति अपना गहरा आभार जताते हुए उनके कार्यों को समाज के लिए एक मिसाल बताया। रक्तवीरों ने स्पष्ट किया कि निरीक्षक अनुराग झारिया जैसे कर्मठ और पूरी तरह समर्पित पुलिस अधिकारी पूरे समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि उनके इन अथक और मानवीय प्रयासों से न केवल आम जनता के बीच पुलिस विभाग की छवि पहले से कहीं अधिक मजबूत और सकारात्मक हुई है, बल्कि पूरे समाज में रक्तदान जैसे महादान के प्रति एक नई और अभूतपूर्व जागरूकता भी बढ़ी है।



विचार लेख



पंडित रविशंकर शास्त्री

पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध से मिलेगी आपको शांति सुख समृद्धि आरोग्यता और मोक्ष

पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे परिवार को सुख-समृद्धि, दीर्घायु, वंश वृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथन के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज सुक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आते हैं। इस दौरान किए गए तर्पण से उन्हें निम्नलिखित लाभ और पुण्य प्राप्त होते हैं:

पितृ ऋण से मुक्ति: हिंदू धर्म में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण नाम के तीन मुख्य ऋण माने गए हैं। श्राद्ध करने से व्यक्ति अपने पितृ ऋण (पूर्वजों के प्रति कर्तव्य) से मुक्त होता है इसीलिए पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों का तर्पण करने से पूर्व देव ऋषि और दिव्य मनुष्य तर्पण करना चाहिए।

मोक्ष और तृप्ति: जल और काले तिल से किया गया तर्पण पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। इससे उन्हें उच्च लोकों की यात्रा में ऊर्जा मिलती है और प्रेत योनि या कष्टों से मुक्ति मिलती है।

पितृदोष का निवारण: जिन कुंडलियों या परिवारों में पितृदोष होता है (जिसके कारण कार्यों में रुकावट आती है), पितृ पक्ष में नियमित तर्पण करने से वह दोष शांत हो जाता है।

वंश की वृद्धि: परिवार में योग्य संतान की प्राप्ति होती है और वंश आगे बढ़ता है।सुख-समृद्धि और धन: व्यापार, नौकरी और धन-धान्य में आ रही रुकावटें दूर होती हैं।

पारिवारिक एवं मानसिक शांति: घर में क्लेश, अकारण बीमारी और अशांति का माहौल खत्म होता है और आपसी प्रेम बढ़ता है।

गरुड पुराण और मार्कण्डेय पुराण में लिखा है कि जब पितर श्राद्ध और तर्पण से तृप्त होते हैं, तो वे अपने वंशजों कोआयु, प्रजा (संतान), धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, तर्पण न करने से पितर निराश होकर लौटते हैं, जिससे घर में दारिद्रता और अशांति आ सकती है।

किस विधि से करें पितरों का तर्पण किस दिशा में करना चाहिए?

दक्षिण दिशा : पितरों का तर्पण हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है।

किस स्थान पर करना चाहिए?

सर्वोत्तम स्थान: किसी पवित्र नदी का किनारा, तीर्थ स्थल